मनदीप कौर, मैनेजिंग डायरैक्टर

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ

आज तक आमने-सामने

पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा

Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com

RNI No-Punhin2013/54688 1-15 SEPTEMBER 2025

एस. के. सक्सैना, मुख्य संपादक

साल 2025 /संपादक एसके सक्सैना / www aajtakaamnesaamne.com /Help Line 9878552070

ट्रक चालक के अपहरण में घिरा पूजा खेड़कर का परिवार

नवी मुंबई (एजंसी)–नवी मुंबई में सड़क विवाद के बाद अपहृत किए गए एक ट्रक चालक को पुलिस ने पुणे स्थित पूर्व IAS प्रोबेशनर पूजा खेड़कर के घर से बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, शनिवार शाम मुलुंड–आयरौली मार्ग पर कंक्रीट मिक्सर ट्रक चालक प्रह्लाद कुमार (22) का वाहन एक एसयूवी से टकरा गया था। इस दौरान ट्रक चालक और स्कूल सवारों के बीच बहस हो गई। इसके बाद एसयूवी सवार युवक कुमार को पुलिस स्टेशन ले जाने के बहाने जबरन अपने साथ ले गए और वहां से फरार हो गए। शिकायत मिलने पर राबले पुलिस ने रविवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) (अपहरण) के तहत मामला दर्ज किया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने पाया कि चालक को पुणे ले जाया गया है।

भाजपा घुसपैठियों की जमीन हड़पने की साजिश को नाकाम कर देगी : मोदी

कहा, कांग्रेस सेना का समर्थन करने के बजाय आतंकवादियों का समर्थन कर रही है

नई दिल्ली (एजंसी)–प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस देश की सेना का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादियों का समर्थन कर रही है। मोदी ने असम के दारंग जिले के मंगलदई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर घुसपैठियों और राष्ट्र–विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप लगाया।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भाजपा घुसपैठियों की जमीन हड़पने और जनसांख्यिकी बदलने की उनकी साजिश को नाकाम कर देगी। मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, '' कांग्रेस भारतीय सेना का समर्थन करने के बजाय पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकवादियों का समर्थन करती है। वह घुसपैठियों और राष्ट्रविरोधी ताकतों को संरक्षण देती है।%% उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस ने दशकों तक असम पर शासन किया, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी पर ''केवल तीन पुल%% बनाए, जबकि भाजपा नीत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में छह ऐसे पुल बनाए हैं। मोदी ने ''अतिक्रमण की गई भूमि से घुसपैठियों को बाहर निकालने और अब इन भूखंडों पर किसानों के खेती करने संबंधी कदम%% के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की सराहना की। प्रधानमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभर रहा है और असम की विकास दर 13 प्रतिशत है। उन्होंने कहा, '' यह 'डबल इंजन% वाली सरकार के प्रयासों से संभव हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार असम को स्वास्थ्य के केंद्र के रूप में विकसित कर रही हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने में पूर्वोत्तर की बड़ी भूमिका है।

राहुल गांधी का पंजाब दौरा, अमृतसर व गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावितों से मिले

अमृतसर में उनका कांग्रेस नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया

अमृतसर (पंकज)–लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार को अमृतसर और गुरदासपुर जिलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका कांग्रेस नेताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वागत करने वालों में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, सांसद गुरजीत सिंह औजला, पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा सहित अन्य कांग्रेस नेता मौजूद थे। हवाई अड्डे से राहुल गांधी सबसे पहले अमृतसर जिले के बाढ़ प्रभावित कस्बे रमदास रवाना हुए, जहां उन्होंने गुरुद्वारे में माथा टेका और प्रभावित लोगों से मुलाकात की। राहुल गांधी इसके बाद गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित लोगों से बातचीत की और हालात का जायजा लिया।

'ग्रेट निकोबार मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर' परियोजना को जबरदस्ती थोप रही सरकार

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का केंद्र पर निशाना

नई दिल्ली (एजंसी)–कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 'ग्रेट निकोबार मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर' परियोजना एक 'पारिस्थितिकीय आपदा' है, जिसे नरेन्द्र मोदी सरकार जबरदस्ती थोप रही है, जबकि इसकी पर्यावरणीय मंजूरी को अदालतों में चुनौती दी गई है। पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि 'अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम' इस परियोजना के तहत पेड़ों की गणना, कटाई, लट्ठे की ढुलाई और जमीन पर चिह्नांकन के लिए रुचि पत्र (ईओआई) आमंत्रित करने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ा रहा है। कांग्रेस नेता ने 'एक्स' पर कहा, '18 अगस्त, 2022 को, केंद्रीय गृह मंत्रालय के नियंत्रण में आने वाले अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने प्रमाणित किया था कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत सभी व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों की पहचान की जा चुकी है, उनका निपटारा कर लिया गया है, और ग्रेट निकोबार मेगा इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना के लिए भूमि हस्तांतरण हेतु सहमति प्राप्त कर ली गई है। उन्होंने कहा कि 18 दिसंबर 2024 को इस मंजूरी को सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मीना गुप्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। वह केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में सचिव थीं और केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय में एक वरिष्ठ अधिकारी भी रह चुकी हैं। रमेश ने कहा कि उनकी याचिका में कहा गया है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के प्रमाणीकरण में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का अक्षरशः पालन नहीं किया गया है और वास्तव में यह दिसंबर 2006 में संसद द्वारा पारित कानून का बहुत गंभीर उल्लंघन है। कांग्रेस नेता ने कहा, 'इसके बाद 19 फरवरी, 2025 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने अजीब तरीके से कलकत्ता हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर कहा कि उसे प्रतिवादियों की सूची से हटा दिया जाना चाहिए।' हालांकि, उन्होंने दावा किया कि 8 सितंबर 2025 को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने स्थानीय प्रशासन द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का पालन न करने के संबंध में लिटिल और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की जनजातीय परिषद द्वारा उठाए गए कई बिंदुओं पर केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मुख्य सचिव से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी।

बाढ़ प्रभावितों को दिवाली तक मिल जाएंगे मुआवजे के चेक : भगवंत मान

कहा, मैं राज्य के लोगों के साथ खड़ा हूं

चंडीगढ़ (रमन कुमार)–पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक दिन बाद शुक्रवार को फिर सक्रिय हो गए। उन्होंने बाढ़ राहत कार्यों का आकलन करने और राज्य के क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण की योजनाओं को लेकर बैठकें कीं। उन्होंने कहा, मैं पंजाब का मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं दुख मंत्री हूं। मैं राज्य के लोगों के साथ खड़ा हूं, जो बाढ़ के कारण अब तक के सबसे बुरे संकट का सामना कर रहे हैं। दुख साझा करण नाल दुख अद्धा रह जांदा है। सीएम ने कहा कि वह बाढ़ प्रभावित लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनकी सरकार 45 दिनों के भीतर पूरा मुआवजा जारी कर देगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने सभी उपायुक्तों को फसल नुकसान की विशेष गिरदावरी पूरी करने, जान–माल के नुकसान, पशुओं की मौत और घरों को हुए नुकसान की रिपोर्ट जल्द देने और उनका सत्यापन करने का निर्देश दिया है, जिससे हम तुरंत मुआवजा देना शुरू कर सकें।% उन्होंने कहा कि चेक दिवाली तक दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से

मुआवजा देने के काम की निगरानी कर रहा हूं, क्योंकि लोगों को तत्काल राहत की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब फसल नुकसान के लिए सबसे ज्यादा मुआवजा 20 हजार रुपये प्रति एकड़ देगा। उनके साथ राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन और मुख्य सचिव केएपी सिन्हा मौजूद रहे।

जीएसटी सुधारों का लाभ सभी उत्पादों पर मिलेगा : वित्त मंत्री

नई दिल्ली (एजंसी)–केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार देश के प्रत्येक नागरिक के लिए एक बड़ी जीत है। सीतारमण ने रविवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत के प्रत्येक राज्य के अपने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दीपावली से पहले जीएसटी सुधारों को लागू करने के निर्देश से बहुत पहले ही इन्हें लागू करने का निर्णय लिया गया है। चेन्नई सिटीजन्स फोरम द्वारा आयोजित 'उभरते भारत के लिए कर सुधार% कार्यक्रम में अपने संबोधन में सीतारमण ने कहा कि माल एवं सेवा कर का लाभकारी प्रभाव सुबह की शुरुआत से लेकर रात के सोने तक सभी उत्पादों पर रहेगा। कुछ प्रमुख पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि जिन 99 प्रतिशत वस्तुओं पर पहले जीएसटी के तहत 12 प्रतिशत कर लगता था, अब उनपर सिर्फ 5 प्रतिशत कर लगेगा। नए जीएसटी सुधार (2.0) 22 सितंबर से लागू होंगे। जीएसटी परिषद द्वारा 350 से अधिक वस्तुओं पर कर की दरों में कटौती का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने पहले अलग–अलग स्लैब के तहत कर लगाने की प्रथा के बजाय केवल पांच और 18 प्रतिशत के स्लैब लागू किए हैं। हमने व्यापारियों के लिए भी प्रक्रिया को सरल बनाया है। किसी भी

उत्पाद पर 28 प्रतिशत जीएसटी कर नहीं है। व्यापारियों के कर दायरे में वृद्धि का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 में जीएसटी लागू होने से पहले केवल 66 लाख व्यापारी ही कर दाखिल करते थे। लेकिन आज, पिछले आठ साल में 1.5 करोड़ व्यवसाय जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा था। हालांकि जीएसटी लागू होने के बाद, पिछले 8 साल में कर चुकाने वाले व्यवसायों की संख्या बढ़कर 1.5 करोड़ हो गई है। उन्हें एहसास हुआ कि वे इससे लाभान्वित हो पाएंगे। पिछले 8 साल में जीएसटी दाखिल करने वाले 1.5 करोड़ व्यापारियों की यह संख्या भविष्य में और बढ़ेगी।

विदेशी छात्रों के लिए अमेरिका में एंट्री बंद

वाशिंगटन (एजंसी)–अफगानिस्तान में लड़कियों के कॉलेज जाने पर तालिबान की ओर से प्रतिबंध लगाए जाने के बाद बहारा सागरी नाम की युवती ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। बहारा (21) ने कई वर्षों तक प्रतिदिन आठ घंटे तक अंग्रेजी का अभ्यास किया और आखिरकार उसे इलिनॉय के एक निजी लिबरल आर्ट्स कॉलेज में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने का प्रस्ताव मिला। बहारा इस साल अमेरिका पहुंचने की उम्मीद में थीं लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यात्रा प्रतिबंध के कारण उनका सपना एक बार फिर पूरा नहीं हो पाया। बहारा ने कहा, आपको लगता है कि आखिरकार आप अपने सपने की ओर बढ़ रहे हैं लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। ट्रंप प्रशासन ने 19 देशों के नागरिकों

डोनाल्ड ट्रंप का नया आदेश जारी

पर यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं और इन प्रतिबंधों से हजारों विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं, जिनमें से कई ऐसे भी हैं जो अमेरिका आने के लिए काफी समय और पैसा लगाने के बाद अब खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं।

30वें संशोधन पर सियासी घमासान, खड़गे बोले-सरकार का असली मकसद कुछ और...

कहा, चुनावी सुधार के नाम पर लोगों के मतदान के अधिकार को छीनने का प्रयास हो रहा है

नई दिल्ली (एजंसी)–कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को दावा किया कि 130वें संवैधानिक संशोधन संबंधी विधेयक के पीछे असली खेल की मंशा हो सकती है क्योंकि यदि किसी भी मुख्यमंत्री को 30 दिन जेल में रहने पर पद से हटा दिया जाए तो फिर चुनाव की चिंता क्यों होगी। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि चुनावी सुधार के नाम पर लोगों के मतदान के अधिकार को छीनने का प्रयास हो रहा है।

खड़गे ने अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के अवसर पर 'एक्स% पर पोस्ट किया, ''पिछले 11 वर्षों में आरएसएस–भाजपा द्वारा भारत के लंबे समय से पोषित और कड़ी मेहनत से निर्मित लोकतंत्र को खोखला करने का षड्यंत्रकारी प्रयास किया जा रहा है।'' उन्होंने दावा किया कि चुनावी हेराफेरी को ''सुधार'' का जामा पहनाकर, संविधान में निहित सबसे महत्वपूर्ण मतदान के अधिकार को छीनने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा ''बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के माध्यम से लाखों लोगों, विशेष रूप से कमजोर वर्गों को मताधिकार से वंचित करने से लेकर राहुल गांधी द्वारा उजागर की गई निंदनीय ''वोटचोरी'' तक, भाजपा ने लगातार और रणनीतिक रूप से चुनावों की शुचिता को खत्म कर दिया है। खड़गे का दावा है, ''असली खेल 130वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में हो सकता

है। यह प्रस्ताव केंद्र को चुनी हुई राज्य सरकारों को ''भ्रष्ट'' करार देकर गिराने की अनुमति देता है, जिसका आकलन पहले से ही भाजपा की पकड़ वाली एजेंसियों द्वारा आसानी से किया जा सकता है। उनका आरोप है कि यह विधेयक दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, ''जब आप निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को 30 दिनों के भीतर कानूनी तौर पर बर्खास्त कर सकते हैं तो चुनाव की चिंता क्यों करें? इसका संदेश यही प्रतीत होता है।'' उन्होंने कहा, ''इसलिए, इस अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर, आइए, हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं को आरएसएस–भाजपा के चंगुल से बचाने की अपनी प्रतिज्ञा दोहराएं।'' केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच लोकसभा में 'संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025%, 'संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025% और 'जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025% पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को गंभीर अपराध के आरोपों में पद से हटाने का प्रावधान है। संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे और यह समिति अपनी रिपोर्ट अगले संसद सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक पेश करेगी।

संपादकीय

चरित्रहीन, आसामाजिक तत्वों के पनाहगार, भ्रष्टाचारी,घपले बाज,घोर अपराधी, रिश्वतखोर ,गैर कानूनी कार्यों में संलिप्त नेताओं को चुन कर उनसे अच्छाई की आशा रखना कितना उचित?

जरा सोचिए – क्या जनता का स्वार्थ या ...?

राजनीतिक दलों द्वारा सता को हासिल करने हेतु वोटरों को लुभाने हेतु नए नए हथकंडे अपनाना।

चुनाव नजदीक आते ही अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से लालच वश दल बदलना। वोट बैंक के लालच में चोर,डाकू, भ्रष्टाचारी,कामचोर,नशे के सौदागर,घपले बाज,घोर अपराधी, संवेदनशील जुर्मों के अंतर्गत जेलों में सजाएँ काट रहे,रिश्वतखोर, नशेड़ी, चरित्रहीन यूँ कहें सर्व अवगुणों से संपन्न ऐसे लोगों को विजयी बना कर सरकार बनाना कहां तक उचित?। शिक्षा की बात करें तो कुछेक को शपथ भी नही पढ़नी आती एवं शैक्षणिक योग्यता दर्जा चार कर्मचारी से भी कम। सरकार के ऊंचे मंत्री पदों पर विराजमान हो कर उच्च स्तरीय अधिकारियों को कटु वचन बोलना एवं कानूनी मशवरे सिखाना। चोर चोरी से जाए पर हेराफेरी से न जाए के कथनानुसार अवसर की तलाश में रहना। कानूनी बनाने वाले एवं तोड़ने वाले भी खुद =जब खुद कोतवाल तो डर कैसा। जनता के खून पसीने की कमाई से एशो–आराम में एवं सता के नशे में मदहोश हो कर भूल जाना कि हम कौन? यदि देखा जाए कि राजनीतिक एक सद्भावना से सेवा है परंतु ऐसा लगता है कि आजकल राजनीती एक विशेष व्यापार बन कर रह गया है। जो एक बार किसी राजनीतिक पद पर आसीन हो जाता है उसकी संपति एवं ठाठ–बाट में वृद्धि होना लगभग निश्चित हो गया है। इस प्रकार राजनीति में भविष्य अजमाने हेतु अधिकांश प्रचलित हो गया है। क्यों कि इस पद हेतु न ही उचित जैसे ≍ शैक्षणिक योग्यता, मैरिट, चारित्र, पुलिस प्रशासन द्वारा जांच पड़ताल रिपोर्ट डाक्टरी फिटनेस प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की जांच–पड़ताल, शरीरिक चाहिए जब कि दर्जा चार कर्मचारी को नौकरी लेने हेतु कई माप दण्ड़ों से गुजरना होता है। काम अधिक मजदूरी कम नौकरी की अवधि पूरी होने उपरांत पैंशन सुविधा से वंचित जब कि राजनीतिक पदों पर अधिक तनखाह,भले, सहूलतें एवं पांच वर्ष की अवधि पर पैंशन। बुद्धिजीवी वर्ग अनुभव के अनुसार जैसे किसी भी सरकारी पद हेतु मापदंड निर्धारित हैं इसी प्रकार सरकार के प्रतिनिधिमंडल हेतु भी मापदंड अनिवार्य होने चाहिए ताकि सरकार सुयोग्य प्रतिनिधियों की हो। देश के विकास एवं बच्चों के उज्जवल भविष्य के देखते हुए राजनीतिक दलों को भी जांच पड़ताल करके ही प्रत्यक्षियों को चुनाव मैदान में उतारना चाहिए एवं वोटरों को बिना किसी लालच के सुयोग्य प्रत्याक्षी को ही विजयी बना कर अच्छी सरकार बनाना सुनिश्चित करना होगा।

डॉ. मुरुगन ने पंजाब के रूपनगर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का लिया जायजा

किसानों और ग्रामीणों से संवाद करके हर संभव मदद की जाएगी – डॉ. मुरुगन

एस. के. सक्सैना

रूपनगर, सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने आज पंजाब के रूपनगर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दौरा कर स्थिति का गहराई से अवलोकन किया। उन्होंने शाहपुर बेला, हरीवाल, भानुपाली, बेला ध्यानी, नंगल सहित अनेक गाँवों का दौरा कर किसानों, ग्रामीणों, स्थानीय नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद किया। बाढ़ की वजह से कृषि, परिवहन, जलनिकासी और दैनिक जीवन पर पड़े प्रभाव का उन्होंने स्थल पर पानी में पैदल चलकर व ट्रैक्टर और नाव पर जाकर निरीक्षण किया तथा प्रभावित परिवारों की समस्याएँ सुनीं। डॉ. मुरुगन ने किसानों के खेतों में जाकर फसल क्षति का निरीक्षण किया। उन्होंने मक्का, धान सहित अन्य फसलों के नुकसान का जायजा लिया, साथ ही जलभराव और सिल्ट जमा होने से हुई कठिनाइयों का भी अवलोकन किया। किसानों ने उन्हें बताया कि खेतों में पानी भर जाने से खेती प्रभावित हो रही है, सिंचाई व्यवस्था बाधित हुई है और मुख्य मार्गों के कट जाने से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो रही है। किसानों ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यदि समय पर राहत कार्य नहीं किए गए तो अगली फसल पर भी संकट आ सकता है। डॉ. मुरुगन ने उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, 卐आपकी कठिनाइयाँ हमारी प्राथमिकता हैं। केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है। हम स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर आवश्यक कदम उठाएँगे ताकि राहत कार्यों में कोई बाधा न आए। हम हर संभव सहायता प्रदान करेंगे ताकि आप जल्द सामान्य जीवन में लौट सकें।ग्रामीणों ने डॉ. मुरुगन से अनुरोध किया कि गाँवों को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए एक मजबूत पुल का निर्माण कराया जाए ताकि भविष्य में आपदा की स्थिति में आवागमन प्रभावित न हो। उन्होंने बताया कि रास्ते कट जाने से न केवल कृषि कार्य बाधित हो रहे हैं, बल्कि चिकित्सा सहायता, आवश्यक आपूर्ति और रोज़मर्रा की सेवाएँ भी प्रभावित हो रही हैं। डॉ. मुरुगन ने ग्रामीणों की इस माँग को गंभीरता से लिया और आश्वासन दिया कि सरकार आवश्यक प्रक्रियाएँ शुरू कर इस दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और दीर्घकालिक समाधान पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचा जा सके।

केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. एल. मुरुगन ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा को सराहनीय कदम बताते हुए कहा कि

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर बाढ़ की स्थिति का आकलन उच्चस्तरीय टीमें कर रही हैं। केंद्र सरकार इस कठिन समय में प्रभावित किसानों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। डॉ. मुरुगन ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का आश्वासन दिया । डॉ. मुरुगन ने ग्रामीणों द्वारा सेवा कार्यों में दिखाए गए समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि संकट की घड़ी में समाज की एकजुटता ही सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि आपदा की परिस्थितियों में एक–दूसरे का सहयोग करना समाज की मूल भावना को मजबूत करता है। उन्होंने नंगल स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर का दौरा कर वहाँ हुई बाढ़ क्षति का निरीक्षण किया और आवश्यक मरम्मत कार्यों का आश्वासन दिया। साथ ही, उन्होंने दौरे के दौरान राहत सामग्री का वितरण कर प्रभावित परिवारों से संवाद भी किया। ग्रामीणों की सेवा भावना की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में एकजुट रहना समाज की ताकत है। पुल निर्माण, राहत सामग्री वितरण, चिकित्सा सहायता और आवागमन की सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य करेंगी। उन्होंने अपने संवाद में स्पष्ट किया कि सरकार की प्राथमिकता प्रभावित परिवारों को समय पर मदद उपलब्ध कराना, उनकी समस्याओं को सुनना और दीर्घकालिक समाधान लागू करना है। शाम को डॉ. मुरुगन ने रूपनगर के उपायुक्त व प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में राहत कार्यों की स्थिति, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, चिकित्सा सहायता, राहत सामग्री वितरण, आवागमन व्यवस्था और भविष्य की योजना पर गहन चर्चा की गई। डॉ. मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने के लिए उच्चस्तरीय टीमें भेजी हैं। उन्होंने कहा, 卐हमारी प्राथमिकता यह है कि प्रभावित परिवारों को समय पर राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर समन्वित प्रयास करेंगी ताकि राहत कार्य प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सके। कोई भी प्रभावित परिवार मदद से वंचित नहीं रहेगा।卐 टीमों द्वारा तैयार की जा रही रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सहायता और राहत कार्यों को तेज़ गति से लागू किया जाएगा। साथ ही, दीर्घकालिक पुनर्वास योजनाओं पर भी काम शुरू किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी आपदा की स्थिति में बेहतर तैयारी की जा सके डॉ. मुरुगन ने समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राहत कार्यों को समय पर लागू किया जाए और आवश्यक संसाधनों की कमी न होने दी जाए। उन्होंने कहा कि राहत सामग्री की वितरण व्यवस्था पारदर्शी हो, चिकित्सा टीमों को प्रभावी ढंग से तैनात किया जाए और किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुना जाए। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को नकद सहायता, बीज, खाद, जल निकासी व्यवस्था और अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगी। इसके साथ ही, उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राहत कार्यों की निगरानी समय–समय पर की जाए ताकि योजनाओं का सही लाभ प्रभावित परिवारों तक पहुँचे। डॉ. मुरुगन ने कहा कि राहत कार्यों के साथ–साथ दीर्घकालिक पुनर्वास योजना पर भी काम किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए ताकि भविष्य में बाढ़ जैसी आपदा से न्यूनतम नुकसान हो। उन्होंने कहा कि पुल निर्माण, जल निकासी व्यवस्था, सड़क संपर्क, सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना आवश्यक है। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन मिलकर योजनाएँ लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि राहत कार्यों की निरंतर समीक्षा की जाएगी और समय–समय पर स्थिति का जायजा लिया जाएगा ताकि प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुँचे।

भाजपा ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेजी राहत सामग्री

पंजाब के हर वर्ग के सहयोग के लिए चट्टान की तरह खड़ी है भाजपा–सुनील जाखड़

मनदीप कौर

जालंधर, भाजपा जिला जालंधर के अध्यक्ष सुशील शर्मा की अध्यक्षता में भाजपा पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ,कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, के नेतृत्व में पंजाब में बाढ़ की भीषण स्थिति को देखते हुए, भाजपा ने राज्य के सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री ट्रैकों में भरकर भेजी ।इस राहत सामग्री में राशन , पानी की बोतलें, कपड़े, कंबल, तिरपाल, बर्तन, मच्छरदानी, फोल्डिंग बेड,और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्षसुनील जाखड़ ने बताया कि भाजपा का यह कदम पंजाब के लोगों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और समर्थन को दर्शाता है। पार्टी का उद्देश्य बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव मदद प्रदान करना है और उन्हें इस मुश्किल समय में साथ खड़ा होना है सुनील जाखड़ ने कहा कि भाजपा पंजाब के हर वर्ग के लोगों के लिए सहयोग करने के लिए चट्टान की तरह हमेशा खड़ी है।

रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि भाजपा के इस प्रयास से बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी और उन्हें अपने जीवन को सामान्य बनाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आगे भी पंजाब के लोगों के साथ खड़ी रहेगी और उनकी हर संभव मदद करेगी।

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पठानकोट से विधायक अश्विनी शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का पहला फर्ज है कि वह पंजाब और पंजाबियत को मजबूत करें ताकि आने वाले समय में पंजाब के लोग अपना जीवन सुचारु रूप से चला सके उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा पंजाबियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और उनकी हर मुश्किल में और संकट की घड़ी में उनके साथ देगी इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, जालंधर के पूर्व मेयर एवं प्रदेश महामंत्री राकेश राठौर, पूर्व संसदीय सचिव एवंप्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण देव भंडारी, जालंधर के पूर्व सांसद सुशील कुमार रिंकू, पूर्व विधायक शीतल अंगूराल, सरबजीत सिंह मक्कड़ ,जगबीर बराड़ प्रदेश सचिव सूरज भारद्वाज,पूर्व प्रदेश सचिव अनिल सच्चर ,पूर्व जिला अध्यक्ष रमन पब्बी, रमेश शर्मा, सुभाष सूद, रवि महेंद्रू, पार्षद राजीव धींगरा पार्षद पति अमित सिंह संध्या भगवंत प्रभाकर मनजीत सिंह टीटू अश्विनी भाजपा स्पोर्ट्स सेल के प्रदेश अध्यक्ष सनी शर्मा, जिला महामंत्री राजेश कपूर, अशोक सरीन हिकी,अमरजीत सिंह गोल्डी, जिला उपाध्यक्ष मनीष विज, अश्विनी भंडारी, दविंदर कालिया, दर्शन लाल भगत, भूपेंद्र कुमार, दविंदर भारद्वाज,जिला सचिव अमित भाटिया, हितेश स्याल, गोपाल कृष्ण सोनी, सनी शर्मा ,दविंदर सिंह डिंपी लुभाना, मीनू शर्मा ,अनु शर्मा ,शालू कुमारी ,मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार आरके, कुलवंत शर्मा, गुरप्रीत सिंह विकी, आशीष सहगल , संदीप कुमार,क्षितिज ढल, चंदन रखेजा, मनीष बल, सुनील चोपड़ा,कुणाल शर्मा, राजकुमार चौहान, अजय ठाकुर, जॉर्ज सागर, कुलदीप माणक राहुल जमवाल, शिव दर्शन, अभी, अनुज शारदा, विष्णु जोशी, दिनेश महेंद्रु ,अनिल शर्मा, किशन लाल शर्मा ,डॉक्टर विनीत शर्मा, पंकज जुल्का, अजमेर सिंह बादल, अजय जोशी, वह अन्य उपस्थित थे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोबेल पुरस्कार के सही हकदार-एडवोकेट एन.के. वर्मा

कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा

नई दिल्ली, नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। यह उन व्यक्तियों या संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने मानवता के कल्याण, शांति, विज्ञान, साहित्य और समाज की बेहतरी के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया हो। विशेष रूप से शांति पुरस्कार उन नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने युद्ध को रोकने, वैश्विक भाईचारे को बढ़ावा देने और मानवीय सेवा के क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल की हो। पिछले वर्षों में कई राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2009 में परमाणु निरस्त्रीकरण और वैश्विक कूटनीति के प्रयासों के लिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को 1953 में साहित्य के लिए, दक्षिण अफ्रीका के

नेल्सन मंडेला को रंगभेद समाप्त करने में योगदान के लिए, और इज़राइल–मिस्र के नेताओं को कैंप डेविड समझौते के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया आज जब दुनिया युद्ध, आतंकवाद और जलवायु संकट से जूझ रही है, ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल देश के भीतर बल्कि विश्व स्तर पर भी शांति, सहयोग और मानवता की नई परिभाषा गढ़ी है। देश के भीतर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों परिवारों को मुफ्त राशन और कोविड वैक्सीन उपलब्ध करवाई। महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए स्वास्थ्य, पोषण तथा सशक्तिकरण की अनेक योजनाएँ शुरू कीं। जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान जैसी ऐतिहासिक पहलों ने लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार किया। कोविड महामारी के दौरान भारत ने दर्जनों देशों को वैक्सीन और दवाइयाँ उपलब्ध कराईं। संकट की घड़ी में कई देशों को खाद्यान्न और आर्थिक सहायता भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर युद्ध और हिंसा की भर्त्सना की तथा शांति और संवाद पर जोर दिया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहल ने दुनिया को अक्षय ऊर्जा की ओर प्रेरित किया और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक धरोहर का स्वरूप दिया। विश्व मंच पर मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम् (पूरी दुनिया एक परिवार है) की अवधारणा को जीवंत किया। मोदी जी का योगदान पूरी मानवता को दिशा देने वाला है। इसी वजह से उन्हें कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज़ा है। सऊदी अरब ने किंग अब्दुलअज़ीज़ साश , रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल , संयुक्त अरब अमीरात ने ऑर्डर ऑफ ज़ायेद , अफगानिस्तान ने अमीर अमानुल्लाह ख़ान अवार्ड और बहरीन ने किंग हमाद ऑर्डर ऑफ़ द रिनेसां प्रदान कर उनकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता को मान्यता दी है। दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस, जो अमेरिकी मूल के जर्मन फंड मैनेजर और मोबियस कैपिटल पार्टनर्स एलएलपी के संस्थापक हैं, ने कहा कि पीएम मोदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शांतिदूत बन सकते हैं, क्योंकि दुनिया अशांति से गुजर रही है, खासकर वर्तमान पश्चिम एशिया संघर्ष और रूस–यूक्रेन युद्ध के कारण।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन की देखभाल हेतु 481 वैटरनरी टीमें तैनात, 22,000 से अधिक पशुओं का इलाज किया

रमन कुमार

चंडीगढ़, पंजाब के पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि राज्य में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए पंजाब के पशुपालन विभाग की 481 टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुधन की देखभाल और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। प्रत्येक टीम में 4 सदस्य होते हैं, जिनमें एक वैटरनरी अधिकारी, वैटरनरी निरीक्षक/फार्मासिस्ट और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल है।

बाढ़ के गंभीर प्रभावों को उजागर करते हुए श्री खुड्डियां ने बताया कि पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर, फाजिल्का, कपूरथला, बरनाला, बठिंडा, होशियारपुर, तरन तारन, पटियाला, जालंधर, रूपनगर और मोगा सहित 14 जिलों में 504 गायों/भैंसों, 73 भेड़–बकरियां और 160 सूअर मारे गए हैं। इसके अलावा पोल्ट्री शेड ढहने के कारण गुरदासपुर, रूपनगर और फाजिल्का में 18,304 पोल्ट्री पक्षी मरे हैं। उन्होंने बताया कि बाढ़ से लगभग 2.52 लाख पशुधन और 5,88,685 पोल्ट्री पक्षी प्रभावित हुए हैं।

आज तक आमने सामने

RNI NO -PUNHIN0/2013/54688

Printed by Mandeep Kaur, Published by Mandeep Kaur, Owned by Mandeep Kaur & Printed at Dashmash Printers 178-179 Ranjit Nagar, Jalnadhar City, Published 87 Ranjit Nagar Near Bus Stand, Jalandhar, Punjab

Editor Surinder Kumar (SK Saxena)

Responsible for selection of News under the PRB ACT.
All Rights Reserved Reproduction in whole or in Part without Permission in Prohibited, All disputes shall be settled at Jalandhar Jurisdiction only
Faxt No. : 0181-5024001, Conact No : 0181-5077100

आवश्यक सूचना

आज तक आमने-सामने का इस समाचार पत्र में मुद्रित वज्ञापनों (डिस्पले/क्लासीफाईड) के तथ्यों सबंधी कोई दायित्व नहीं है। महारा समाचार पत्र इनको सत्यापित नहीं करता। पाठकों से अनुरोध है कि वे इन विज्ञापनों पर कार्यवाही करने से पूर्व सभी तथ्यों की स्वयं पुष्टि कर लें। -प्रधान संपादक

आईआईटी रोपड़ स्टार्टअप्स को दे रहा है नई उड़ान-`100 स्टार्टअप्स 100 डेज़' पहल के तहत स्प्रिंट नॉर्थ एडिशन का उद्घाटन आईआईएलएम विश्वविद्यालय, गुरुग्राम में हुआ

पंकज

रोपड़, आज भारत की स्टार्टअप यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ा, जब आईआईटी रोपड़ की '100 स्टार्टअप्स 100 डेज़' पहल के तहत स्प्रिंट नॉर्थ एडिशन का उद्घाटन हुआ। यह कार्यक्रम आईआईटी रोपड़ टीआईएफ (आईहब ङ्क अवध, डीएसटी के तहत एनएम–आईसीपीएस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब), अन्नम.एआई (कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्र) और टीबीआईएफ द्वारा संचालित है। कार्यक्रम की शुरुआत आईआईटी रोपड़ टीआईएफ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राधिका त्रिखा ने डीपटेक इकोसिस्टम के निर्माण के अवध के मिशन पर प्रकाश डालते हुए की। आईआईएलएम विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के निदेशक डॉ. रवि कुमार जैन ने स्वागत भाषण दिया, जिसके बाद आईआईटी रोपड़ टीआईएफ के मुख्य नवाचार अधिकारी डॉ. मुकेश केस्टवाल ने अवध के प्रमुख कार्यक्रमों स्प्रिंट और 100 स्टार्टअप्स 100 डेज़ पर अंतर्दृष्टि साझा की, जिसमें ?17 करोड़ के निवेश और बाहरी निवेशकों से ?110 करोड़ से अधिक जुटाए जाने के साथ 160 से अधिक स्टार्टअप्स के पोर्टफोलियो की वृद्धि का उल्लेख किया गया। व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशन के जल परिषद के अध्यक्ष श्री किशन गोयनका और डीएसटी एनएम–आईसीपीएस की वरिष्ठ वैज्ञानिक–सी सुश्री तनुश्री शर्मा ने सभा को संबोधित किया, पायलट नीरज शेखावत, राष्ट्रीय प्रभारी – अनुसंधान और नीति, भाजपा किसान मोर्चा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद उद्घाटन पैनल और मुख्य सत्र की शुरुआत आईआईएलएम विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. (डॉ.) पद्मकली बनर्जी के भाषण से हुई। राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रेखा शर्मा ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में आईआईटी रोपड़ की तीव्र प्रगति की सराहना की। उन्होंने बताया कि मई में स्प्रिंट हरियाणा शुरू करने के मात्र तीन महीनों के भीतर ही, यह पहल हैदराबाद

और गुरुग्राम तक फैल चुकी है और उत्तरी क्षेत्र से 13 आशाजनक स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत को नवाचार और उद्यमिता का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए इस तरह के बड़े पैमाने पर, तेज़ गति वाले प्रयास बेहद ज़रूरी हैं। इस अवसर पर, आईआईटी रोपड़ के निदेशक प्रो. राजीव आहूजा ने अपने वर्चुअल संबोधन में 100 स्टार्टअप्स 100 डेज़ को गति, पैमाने और स्थिरता के साथ उद्यमियों को सशक्त बनाने का एक आंदोलन बताया। आईहब – अवध और अन्नम.एआई के परियोजना निदेशक डॉ. पुष्पेंद्र सिंह ने डीप–टेक स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने और भारत को एक वैश्विक अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए शुरुआती पूंजी और एक समर्पित निधि की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण चेक और प्रमाणन समारोह था, जहाँ जेनेसिस ईआईआर कार्यक्रम के 13 चयनित स्टार्टअप और 3 नवप्रवर्तकों को उनके अभूतपूर्व विचारों और उद्यमशीलता की भावना के लिए सम्मानित किया गया। 卐सीमाओं से परे- डीपटेक निवेश के भविष्य को खोलना卐 विषय पर एक उच्चस्तरीय पैनल चर्चा हुई, जिसमें सुश्री माया शेरमन (भारत में इज़राइल दूतावास), सुश्री नेमेसिसा उज्जैन (द सर्कल एफसी), सुश्री नेहा मल्होत्रा (मेरिटएक्स वेंचर्स), श्री मयंक कुमार (नैसकॉम), और श्री हिमांशु जोशी (एआईएम नीति आयोग) जैसे प्रमुख लोग शामिल थे, जिसका संचालन श्री संतोष शर्मा (बुकमायजेट) ने किया। इस सत्र में डीपटेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक स्तर पर विस्तार के अवसरों पर चर्चा की गई। इसके बाद एक संस्थापक वार्ता हुई, जिसमें डॉ. प्रीत संधू (एवीपीएल इंटरनेशनल) और श्री खालिद वानी (वन कैपिटल लिमिटेड और केडब्ल्यूसीजी) ने अपनी उद्यमशीलता की यात्रा साझा की। इस कार्यक्रम में लाइव स्टार्टअप पिच और प्रमुख पहलों का अनावरण भी शामिल था, जिसमें अवध प्रगति रिपोर्ट, नैसकॉम के सहयोग से डीटीसी एक्सेलरेट – क्लाइमेटटेक का शुभारंभ, और भारत इनोवेट 2026 पर एक अपडेट शामिल था। यह शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य जून 2026 में फ्रांस में भारत के शीर्ष 100 नवाचारों को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना और उनका विस्तार करना है। दिन का समापन परिणामों की घोषणा और आईआईएलएम विश्वविद्यालय के इनक्यूबेशन सेंटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रो. (डॉ.) सौरभ त्रिवेदी द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। उन्होंने 50 से अधिक वेंचर कैपिटल भागीदारों, 40 से अधिक इनक्यूबेटरों, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय स्टार्टअप हब, भाषिणी, स्टार्टअप इंडिया, इंडिया एआई और सीफंड सहित प्रमुख सरकारी एंकरों के समर्थन को स्वीकार किया, जिसमें उद्योग, स्टार्टअप और सरकार के 130 से अधिक हितधारकों ने भाग लिया।

जन्म दिन पर विशेष : आदरणीय मोहन भागवत जी

नरेंद्र मोदी
प्रधान मंत्री

आज 11 सितंबर है। यह दिन अलग-अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्वबंधुत्व का संदेश दिया और दूसरी स्मृति है 9/11 का आतंकी हमला, जब विश्व बंधुत्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्मदिवस है जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है।

संघ परिवार में जिन्हें परम पूजनीय सरसंघचालक के रूप में श्रद्धाभाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है।

यह एक सुखद संयोग है कि इसी साल संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। मैं भागवत जी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें।

मेरा मोहन भागवत जी के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे उनके पिता, स्वर्गीय मधुकरराव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में मधुकरराव जी के बारे में विस्तार से लिखा भी है। वकालत के साथ-साथ मधुकरराव जी जीवनभर राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित रहे। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य की मजबूत नींव रखी।

मधुकरराव जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि अपने पुत्र मोहनराव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकरराव ने मोहनराव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी।

भागवत जी का पूरा जीवन सतत प्रेरणा देने वाला रहा है। वे 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। सामान्य जीवन में प्रचारक शब्द सुनकर ये भ्रम हो जाता है कि कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जो संघ को जानते हैं उनको पता है कि प्रचारक परंपरा संघ कार्य की विशेषता है। गत 100 वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक-युवतियों ने अपना घर-परिवार त्याग करके पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भागवत जी भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी हैं।

भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत जी ने आपातकाल-विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में मोहन भागवत जी के कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेहपूर्वक याद करते हैं। इसी कालखंड में मोहन भागवत जी ने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के कार्य में समर्पित रहे।

वर्ष 2000 में वे सरकार्यवाह बने और यहाँ भी भागवत जी ने अपनी अनोखी कार्यशैली से हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभाला।

2009 में वे सरसंघचालक बने और आज भी अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। भागवत जी ने राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि रखा।

सरसंघचालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है। यह एक पवित्र विश्वास है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्वों ने आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है। असाधारण व्यक्तियों ने इस भूमिका को व्यक्तिगत त्याग, उद्देश्य की स्पष्टता और माँ भारती के प्रति अटूट समर्पण के साथ निभाया है। यह गर्व की बात है कि मोहन भागवत जी ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है, बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई और सहृदय नेतृत्व भी जोड़ा है।

भागवत जी का युवाओं से सहज जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। वे लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं, और संवाद करते रहते हैं। श्रेष्ठ कार्य पद्धति को अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, ये मोहनजी की बहुत बड़ी विशेषता रही है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखते हैं तो संघ की 100 साल की यात्रा में भागवत जी का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। चाहे वो गणवेश परिवर्तन हो, संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव हो, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए।

कोरोना काल में मोहन भागवत जी के प्रयास विशेष रूप से याद आते है। उस कठिन समय में उन्होंने स्वयंसेवकों को सुरक्षित रहते हुए समाजसेवा करने की दिशा दी और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने पर बल दिया। उनके मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों तक हरसंभव सहायता पहुँचाई, जगह-जगह मेडिकल कैंप लगाए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों और वैश्विक विचार को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्थाओं को विकसित किया। हमें कई स्वयंसेवकों को खोना भी पड़ा, लेकिन भागवत जी की प्रेरणा ऐसी थी कि अन्य स्वयंसेवकों की दृढ़ इच्छाशक्ति कमजोर नहीं पड़ी।

इस वर्ष की शुरुआत में, मैंने नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान मैंने कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है, जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। इस अक्षयवट वृक्ष की जड़ें इसके मूल्यों की वजह से बहुत गहरी और मजबूत हैं। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में जिस समर्पण से मोहन भागवत जी जुटे हुए हैं, वो हर किसी को प्रेरणा देता है।

समाज कल्याण के लिए संघ की शक्ति के निरंतर उपयोग पर मोहन भागवत जी का विशेष बल रहा है। इसके लिए उन्होंने पंच परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें स्व बोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुम्ब प्रबोधन और पर्यावरण के सूत्रों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। देश और समाज के लिए सोचने वाले हर भारतवासी को पंच परिवर्तन के इन सूत्रों से अवश्य प्रेरणा मिलेगी।

संघ का हर कार्यकर्ता वैभव संपन्न भारत माता का सपना साकार होते देखना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए जिस स्पष्ट विज़न और ठोस एक्शन की जरूरत होती है, मोहन जी इन दोनों गुणों से परिपूर्ण हैं।

मोहन जी के स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता ये है कि वो मृदुभाषी हैं। उनमें सुनने की भी अद्भुत क्षमता है। यह विशेषता न केवल उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में संवेदनशीलता और गरिमा भी लाती है।

मोहन जी, हमेशा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के प्रबल पक्षधर रहे हैं। भारत की विविधता और भारत भूमि की शोभा बढ़ा रही अनेक संस्कृतियों और परंपराओं के उत्सव में भागवत जी पूरे उत्साह से शामिल होते हैं। वैसे बहुत कम लोगों को ये पता है कि मोहन भागवत जी अपनी व्यस्तता के बीच संगीत और गायन में भी रुचि रखते है। वे विभिन्न भारतीय वाद्ययंत्रों में भी निपुण हैं। पठन-पाठन में उनकी रुचि, उनके अनेक भाषणों और संवादों में साफ दिखाई देती है।

पिछले दिनों देश में जितने सफल जन-आंदोलन हुए चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोहन भागवत जी ने पूरे संघ परिवार को इन आंदोलनों में ऊर्जा भरने के लिए प्रेरित किया। मैं पर्यावरण से जुड़े प्रयासों और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को जानता हूँ। मोहन जी का बहुत जोर आत्मनिर्भर भारत पर भी है।

कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो जाएगा। यह भी सुखद संयोग है कि विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन आ रहे हैं।

यह भारत और विश्वभर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक युवा स्वयंसेवक से लेकर सरसंघचालक तक की उनकी जीवन यात्रा उनकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है।

मैं माँ भारती की सेवा में समर्पित मोहन भागवत जी के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की पुनः कामना करता हूँ। उन्हें जन्मदिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने पटना में एपीडा के पहले कार्यालय का उद्घाटन किया

सोनू

नई दिल्ली, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने बिहार को कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात के केंद्र में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 11 सितंबर, 2025 को पटना, बिहार में आयोजित बिहार आइडिया फेस्टिवल में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी और उद्योग मंत्री श्री नीतीश मिश्रा के साथ-साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, एपीडा नेतृत्व, उद्यमी, एफपीओ और किसान समूह भी उपस्थित थे। बिहार का समृद्ध कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र शाही लीची, जर्दालू आम, मिथिला मखाना और मगही पान से लेकर मुख्य अनाज और फलों व सब्जियों के विविध मिश्रण तक, उच्च-संभावना वाले कृषि उत्पादों की एक विविध श्रृंखला के अनुकूल है। इनमें से कई उत्पादों को मिले भौगोलिक संकेत (जीआई) टैग उनकी वैश्विक अपील को बढ़ाते हैं, जिससे बिहार को अंतर्राष्ट्रीय कृषि-व्यापार क्षेत्र में एक अद्वितीय बढ़त मिलती है।

टेगोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के संस्थापक स्वर्गीय श्री कंवल किशोर शर्मा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई

रवदिर कुमार

गुरदासपुर, टेगोर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन्स के संस्थापक स्वर्गीय श्री कंवल किशोर शर्मा जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्य, प्रबंधन, स्टाफ और भारत विकास परिषद के सदस्य उपस्थित थे। परिवार के सदस्यों और उनके मित्रों ने उनके जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इसके अलावा, जरूरतमंद लोगों के बीच राशन वितरण किया गया, जो स्वर्गीय श्री कंवल किशोर शर्मा जी की याद में एक महत्वपूर्ण पहल थी। सभा में उपस्थित सभी लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे स्वर्गीय श्री कंवल किशोर शर्मा जी को अपने चरणों में स्थान दें।

केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने यमुनानगर में यमुना नदी के तट पर हुए भूमि कटाव का जायजा लिया

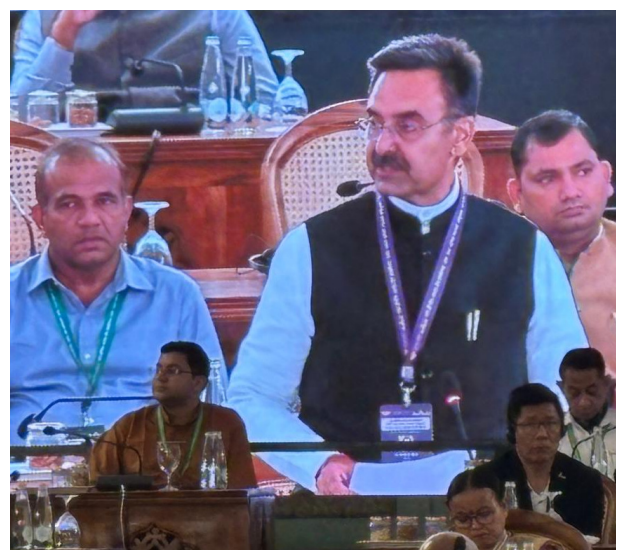

यमुनानगर में भूमि कटाव क्षेत्रों का दौरा, प्रभावितों को मिलेगी विशेष मदद – वी. सोमन्ना

एस. के. सक्सैना

यमुनानगर, केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने आज यमुनानगर जिले के लापरा, टापू कमालपुर और उन्हेडी गांवों का दौरा कर यमुना नदी के तट पर हुए भूमि कटाव का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नदी तटबंधों को और मजबूत किया जाए ताकि भूमि कटाव रोका जा सके। केंद्रीय राज्य मंत्री ने ग्रामीणों और किसानों को आश्वस्त किया कि भारी वर्षा से हुए नुकसान की सरकार विशेष भरपाई करेगी और प्रभावित परिवारों को समय पर राहत पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के निर्देश दिए हैं और केंद्र व राज्य सरकार मिलकर राहत एवं पुनर्वास कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। वी. सोमन्ना ने कहा कि पीएम मोदी ने प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकानों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, स्कूलों का पुनर्निर्माण और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से सहायता शामिल है। उन्होंने कहा कि किसानों को देश का अन्नदाता मानते हुए सरकार संकट की घड़ी में हर संभव आर्थिक मदद करेगी। इस मौके पर हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री कंवर पाल ने भी ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि किसी भी प्रभावित किसान या नागरिक को राहत से वंचित नहीं रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने फसल और मकानों के नुकसान की भरपाई के लिए स्पष्ट मानक तय कर दिए हैं और राज्य सरकार पूरी तत्परता से कार्य कर रही है। इस अवसर पर उपायुक्त पार्थ गुप्ता, मेयर सुमन बहमनी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सपरा, अतिरिक्त उपायुक्त नवीन आहूजा, एसडीएम विश्वनाथ, जिला राजस्व अधिकारी तरुण सहोता, सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता रवि शंकर मित्तल, कार्यकारी अभियंता विनोद कुमार, डीडीपीओ नरेन्द्र सिंह, डीआईपीआरओ डॉ. मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी और भाजपा के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण बने सीपीए जोन-2 के चेयरपर्सन

मनदीप कौर

चंडीगढ़, हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के भारतीय क्षेत्र के जोन-2 के संयोजक/चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। यह घोषणा सीपीए के 11वें भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। श्री बिरला सीपीए भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष भी हैं। सीपीए के भारतीय क्षेत्र में भारतीय संसद तथा 31 विधान मंडल शामिल हैं। गौरतलब है कि सीपीए के भारतीय क्षेत्र के 9 जोन हैं। इनमें से हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण को जिस जोन-2 का संयोजक/चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, उसमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और पंजाब के विधान मंडल शामिल हैं। श्री कल्याण की यह नियुक्ति सितंबर 2025 से अगस्त 2026 तक की अवधि के लिए की गई है। इस नियुक्त के लिए विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला का आभार व्यक्त किया। वहीं, हरियाणा विधान सभा के उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा ने श्री कल्याण को बधाई दी है। बता दें कि बेंगलुरु में आयोजित सम्मेलन में देश भर के विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। हरियाणा का प्रतिनिधित्व विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण और उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा कर रहे हैं।

हिन्दी दिवस पर केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का संदेश

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड चल रहा है

हिंदी दिवस पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा, हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाएं तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बनें

मिलकर चलो, मिलकर सोचो, मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है

डिजिटल इंडिया, ई-गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में मोदी सरकार भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम बना रही है

प्रिय देशवासियों,

आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ।

अपना भारत मूलतः भाषा–प्रधान देश है। हमारी भाषाएँ सदियों से संस्कृति, इतिहास, परंपराओं, ज्ञान–विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने की सशक्त माध्यम रही हैं। हिमालय की ऊँचाइयों से लेकर दक्षिण के विशाल समुद्र तटों तक, मरुभूमि से लेकर बीहड़ जंगलों और गाँव की चौपालों तक, भाषाओं ने हर परिस्थिति में मनुष्य को संवाद और अभिव्यक्ति के माध्यम से संगठित रहने और एकजुट होकर आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है।

मिलकर चलो, मिलकर सोचो और मिलकर बोलो, यही हमारी भाषाई–सांस्कृतिक चेतना का मूल मंत्र रहा है।

भारत की भाषाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि उन्होंने हर वर्ग और समुदाय को अभिव्यक्ति का अवसर दिया। पूर्वोत्तर में बीहू का गान, तमिलनाडु में ओवियालू की आवाज, पंजाब में लोहड़ी के गीत, बिहार में विद्यापति की पदावली, बंगाल में बाउल संत के भजन, कजरी गीत, भिखारी ठाकुर की 'बिदेशिया', इन सबने हमारी संस्कृति को जीवन्त और लोककल्याणकारी बनाया है।

मेरा स्पष्ट मानना है कि भाषाएँ एक दूसरे की सहचर बनकर, एकता के सूत्र में बंधकर आगे बढ़ रही हैं। संत तिरुवल्लुवर को जितनी भावुकता से दक्षिण में गाया जाता है, उतनी ही रुचि से उत्तर में पढ़ा जाता है। कृष्णदेवराय जितने लोकप्रिय दक्षिण में हुए, उतने ही उत्तर में भी हुए। सुब्रमण्यम भारती की राष्ट्रप्रेम से ओत–प्रोत रचनाएँ हर क्षेत्र के युवाओं में राष्ट्रप्रेम को प्रबल बनाती है। गोस्वामी तुलसीदास को हर एक देशवासी पूजता है, संत कबीर के दोहे तमिल, कन्नड़ और मलयालम अनुवादों में भी पाए जाते हैं। सूरदास की पदावली दक्षिण भारत के मंदिरों और संगीत परंपराओं में आज भी प्रचलित है। श्रीमंत शंकरदेव, महापुरुष माधवदेव को हर एक वैष्णव जानता है। और, भूपेन हजारिका को हरियाणा का युवा भी गुनगुनाता है।

गुलामी के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएँ प्रतिरोध की आवाज बनीं। आजादी के आंदोलन के राष्ट्रव्यापी बनने में हमारी भाषाओं की बड़ी भूमिका रही। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, ग्राम–देहात की भाषाओं को आजादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ

ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाट्यकारों ने लोकभाषाओं में, लोककथाओं में, लोकगीतों और लोकनाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वन्दे मातरम् और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान के प्रतीक बने।

जब देश आजाद हुआ, तब हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए इस पर विस्तार से विचार–विमर्श किया और 14 सितम्बर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया है कि हिंदी का प्रचार–प्रसार हो और वह भारत की सामासिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्रसंघ का मंच हो,

चाहे जी–20 का सम्मेलन हो, स्टेज में संबोधन हो, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढाया है। मोदी जी ने आजादी के अमृत काल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के लिए जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमें अपनी संवाद और आपसी संपर्क भाषा के रूप में भारतीय भाषा को अपनाना चाहिए।

राजभाषा हिंदी ने 76 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं। राजभाषा विभाग ने अपनी स्थापना के स्वर्णिम 50 वर्ष पूर्ण कर हिंदी को जनभाषा और जनचेतना की भाषा बनाने का अद्भुत कार्य किया है।

2014 के बाद से सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को निरंतर बढ़ावा दिया गया है। 2024 में हिंदी दिवस पर 'भारतीय भाषा अनुभाग' की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के बीच सहज अनुवाद सुनिश्चित करना है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बनें। डिजिटल इंडिया, ई–गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं।

मित्रों, भाषा सावन की उस बूँद की तरह है, जो मन के दुःख और अवसाद को धोकर नई उर्जा और जीवन शक्ति देती है। बच्चों की कल्पना से गढ़ी गई अनोखी कहानियों से लेकर दादी–नानी की लोरियों और किस्सों तक, भारतीय भाषाओं ने हमेशा समाज को जिजीविषा और आत्मबल का मंत्र दिया है।

मिथिला के कवि विद्यापति जी ने ठीक ही कहा–

देसिल बयना सब जन मिट्ठा।

अर्थात् अपनी भाषा सबसे मधुर होती है।

आइए, हिंदी दिवस के इस अवसर पर हम हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करने और उन्हें साथ लेकर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी तथा विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ें।

आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। वंदे मातरम्।

आईआईटी रोपड़ के स्वायत्त मौसम केंद्र (एडब्ल्यूएस) ने सीएसआर यूनिवर्स सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 जीता

पंकज

रोपड़, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत आईआईटी रोपड़ की एएनएनएएम.एआई फाउंडेशन को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित 5वें सामाजिक प्रभाव सम्मेलन और पुरस्कार में 'सामाजिक भलाई हेतु प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता' श्रेणी में सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार स्वायत्त मौसम केंद्र स्मार्ट जलवायु निगरानी समाधान परियोजना को मान्यता देता है, जो एक गहन तकनीकी नवाचार है जिसे किसानों को वास्तविक समय, अति–स्थानीय मौसम डेटा और एआई–संचालित अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस इकाइयाँ कम लागत वाली, सौर ऊर्जा से संचालित और आईओटी सेंसर से सुसज्जित हैं जो वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति और मिट्टी की स्थिति का डेटा एकत्र करती हैं। यह जानकारी, एआई

–आधारित पूर्वानुमान विश्लेषण के साथ मिलकर, किसानों को फसल नियोजन, सिंचाई, कीट नियंत्रण और संसाधन प्रबंधन पर सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। जलवायु परिवर्तनशीलता और फसल हानि की चुनौतियों का समाधान करके, एडब्ल्यूएस जलवायु–प्रतिरोधी और टिकाऊ कृषि के निर्माण हेतु एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हो रहा है। सोशल इम्पैक्ट अवार्ड 2025 का विषय था इम्पैक्ट 2.0: भारत की प्रगति की अगली लहर को मापना , जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी, साझेदारियों और नवीन वित्तपोषण की भूमिका पर विशेष बल दिया गया। सम्मेलन में 80 से अधिक प्रख्यात वक्ताओं, 200 से अधिक प्रतिनिधियों, उद्योग जगत के नेताओं, नीति–निर्माताओं और 10 से अधिक संसद सदस्यों ने भाग लिया। इसमें मुख्य भाषण, पैनल चर्चा, स्पॉटलाइट वार्ता और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि एवं स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों में प्रभावशाली नवाचारों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियाँ शामिल थीं। पुरस्कार समारोह में उन संगठनों, परोपकारी व्यक्तियों, स्टार्टअप्स और सामाजिक उद्यमों को सम्मानित किया गया जिन्होंने समाज में ठोस और सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में योगदान दिया है। आईआईटी रोपड़ को मिला यह सम्मान ग्रामीण सशक्तिकरण, स्थिरता और सामाजिक कल्याण के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एडब्ल्यूएस परियोजना की सफलता इस बात का प्रमाण है कि भारतीय संस्थानों के नवाचार न केवल समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं, बल्कि खाद्य सुरक्षा और जलवायु अनुकूलन जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की भी क्षमता रखते हैं।

युद्ध नशे के विरुद्ध-कमिश्नरेट पुलिस ने हेरोइन, अवैध शराब और नशीली गोलियों सहित 7 गिरफ्तार

रमन कुमार

जालंधर, पंजाब सरकार की ' युद्ध नशे के विरुद्ध ' मुहिम के तहत जलंधर कमिश्नरेट पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को 150 ग्राम हेरोइन, 20,250 मिलीलीटर अवैध शराब और 31 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस कमिश्नर श्रीमती धनप्रीत कौर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार की नशा विरोधी मुहिम के तहत शहर में कई स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसके दौरान 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ विभिन्न थानों में 6 मामले दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तारी के दौरान इन व्यक्तियों से 150 ग्राम हेरोइन, 20,250 मिलीलीटर शराब और 31 नशीली गोलियां बरामद की गईं। उन्होंने आगे बताया कि नशे की सप्लाई को रोकने के साथ–साथ नशे की दलदल में फंसे 6 व्यक्तियों के पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए उन्हें नशा छुड़ाने वाले केंद्रों में भर्ती करवाया गया है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां

ड्रग माफिया के लिए एक सख्त संदेश हैं कि नशे के नेटवर्क से जुड़े व्यक्तियों की जांच कर उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में भी जारी रहेंगी, ताकि पंजाब से नशे को जड़ से खत्म किया जा सके।

ईपीएफ पेंशनरों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने का अनुरोध - पंकज कुमार

एस. के. सक्सैना

जालंधर–कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर के रीजनल कमिश्नर श्री पंकज कुमार ने बताया इस कार्यालय के अधीन आने वाले चारो जिलो जालंधर, कपूरथला, नवांशहर और होशियारपुर के सभी पेंशनरो से अनुरोध किया जाता है कि जिन पेंशनरो ने अब तक अपना आधार से संबंधित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं कराया है, वे जल्द से जल्द अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र क्षेत्रीय कार्यालय, जालंधर, जिला कार्यालय फगवाड़ा एवं जिला कार्यालय होशियारपुर या अपने बैंक अथवा अपने नजदीकी सुविधा सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर में जमा कराये, अन्यथा उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। आधार से संबंधित डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने के लिये पेंशनरों को अपना बैंक खाता, आधार कार्ड, पीपीओ संख्या और मोबाइल फोन साथ लेकर जाए । रीजनल कमिश्नर श्री पंकज कुमार ने उपरोक्त विषय के अतिरिक्त यह भी ध्यान में आया है कि पेंशनर के मृत्योपरांत भी उनके परिवार

वाले इसकी सूचना जालंधर कार्यालय में समय पर नहीं दे रहे है, जिस वजह से विधवा/नामित/बच्चों को पेंशन जारी करने में विलंब होता है। अतः सभी संबंधित पेंशनधारको से अनुरोध है कि इसकी सूचना शीघ्रातिशीघ्र दे, जिससे कार्यालय अग्रिम कार्यवाही कर सके । पेंशनर किसी भी तरह कि जानकारी व पूछताछ के लिए जालंधर कार्यालय के दूरभाष संख्या 0181–4156685 व 0181–4156686 या जीवन प्रमाण के वेबसाइट https:/jeevanpramaan.gov.in पर संपर्क कर सकते है अथवा कार्य दिवस (सोमवार से शुक्रवार तक) पर कार्यालय समय में अधिक जानकारी हेतु संपर्क कर सकते हैं।

बाढ़ पीड़ितों को राहत बनेगी भाजपा की प्राथमिकता- डॉ. सुभाष शर्मा

पंजाब को दिए पैकेज को लेकर श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार

कैप्टन सुभाष चंद्र

चंडीगढ़, हाल ही में आई भीषण बाढ़ ने श्री आनंदपुर साहिब विधानसभा क्षेत्र के नानग्रां, बेला ध्यानी, भनाम , बुंगा, कल्याणपुर और प्लासी सहित अनेक गांवों को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। फसलें बर्बाद हो गईं, घरों में पानी भर गया और लोगों का जनजीवन अस्त–व्यस्त हो गया। ग्रामीण रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर सुरक्षित आशियाने तक के लिए जूझ रहे हैं। इस आपदा से हताश बाढ़ पीड़ितों की आवाज़ सुनने व उन्हें राहत देने के लिए भाजपा के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ. सुभाष शर्मा खुद गांव–गांव पहुंच रहे हैं । डॉ. शर्मा ने प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जाना व राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने खेतों में पानी से हुए नुकसान और घरों की क्षति का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर समस्याओं को हल करने की अपील की और कहा कि भाजपा व केंद्र सरकार हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़ी है। डॉ. शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के लिए पहले से ही 12,000 करोड़ रुपये आपदा प्रबंधन हेतु स्वीकृत किए थे और अब अतिरिक्त 1,600 करोड़ रुपये का फौरी राहत पैकेज भी दिया है। उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की संवेदनशीलता और पंजाब के लोगों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने आश्वासन दिया कि फसलों, पशुओं और मकानों के हुए नुकसान का पूरा मुआवजा प्रभावित परिवारों तक पहुंचाया जाएगा। ग्रामीणों की आवाज़–बेला ध्यानी गांव में ग्रामीणों ने बताया कि पक्का पुल न होने के कारण बाढ़ के समय उनकी मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। डॉ. शर्मा ने भरोसा दिलाया कि इस मामले को वह केंद्र सरकार तक पहुंचाकर शीघ्र कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे। वहीं, प्लासी गांव में डंगे (बाढ़ सुरक्षा बांध) की समस्या को लेकर लोगों ने चिंता जताई। डॉ. शर्मा ने मौके पर ही अधिकारियों से बात कर इस समस्या के त्वरित समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नारा नहीं बल्कि धरातल पर दिखाई देने वाला संकल्प है। केंद्र सरकार पंजाब को इस आपदा से उबारने के लिए हरसंभव कदम उठा रही है ग्रामीण इलाके के बाद उन्होंने नांगल के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर को सतलुज झील के उफान से हुए नुकसान का जायजा भी लिया तथा श्री सनातन धर्म सभा के प्रधान रमेश गुलाटी तथा अन्य पदाधिकारी को भरोसा दिलाया कि जल्द ही मंदिर की सुरक्षा के लिए अनिवार्य कार्य शुरू करने से पहले आईईटी रूपनगर के विशेषज्ञों से भू सर्वेक्षण करवाया जाएगा। इस दौरान ही उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंध बोर्ड के अध्यक्ष से भी बात करते हुए कहा कि बीबीएमबी भी जरूर मंदिर की सुरक्षा के लिए योगदान सुनिश्चित करे।

स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म संसद में भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से सम्पूर्ण विश्व को परिचित कराया -डा. श्रीप्रकाश मिश्र

स्वामी विवेकानंद के शिकागो विश्व धर्म संसद के उद्बोधन की 132 वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में मातृभूमि शिक्षा मंदिर द्वारा सनातन धर्म संवाद कार्यक्रम मातृभूमि सेवा मिशन के तत्वावधान में संपन्न

एस. के. सक्सैना

कुरुक्षेत्र, ८ स्वामी विवेकानंद का शिकागो भाषण न केवल अलंकृत शब्दों का संग्रह था, बल्कि भारत के प्रति विश्व के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारतीय समाज में विश्वास को पूरी तरह से बदल दिया और नया रूप दिया। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म संसद में भारतीय संस्कृति की वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से सम्पूर्ण विश्व को परिचित कराया। सभी धर्मों का सम्मान करने वाली भारत की सदियों पुरानी धर्म संस्कृति का परिचय विवेकानंद ने इस प्रकार दिया कि उन कुछ क्षणों मे ही भारत का नाम, जिसे कभी विश्व उपहास की दृष्टि से देखता था, आध्यात्मिक उत्कृष्टता के शीर्ष पर स्थापित हो गया। यह विचार स्वामी विवेकानंद के शिकागो विश्व धर्म संसद के उद्बोधन की 132 वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में मातृभूमि शिक्षा मंदिर द्वारा आयोजित सनातन धर्म संवाद कार्यक्रम में मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डा. श्रीप्रकाश मिश्र ने व्यक्त किये। कार्यक्रम का शुभारम्भ मातृभूमि शिक्षा मंदिर के विद्यार्थियों द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र के समक्ष विश्व मंगल की प्रार्थना से हुआ। मातृभूमि शिक्षा मंदिर के विद्यार्थियों ने स्वामी विवेकानंद के जीवन एवं कार्य से संबंधित अनेक प्रेरक प्रसंग एवं संस्मरण प्रस्तुत किये। सनातन धर्म संवाद कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मातृभूमि सेवा मिशन के संस्थापक डा. श्रीप्रकाश मिश्र ने कहा स्वामी विवेकानंद भारत के ऐसे महापुरुष है जिन्होंने भारतीय संस्कृति और यहाँ की आध्यात्मिक चेतना का परचम पूरे विश्व मे फहराया है। अपने ज्ञान, संकल्प शक्ति तथा आत्मबल के माध्यम से ना केवल उन्होंने भारत के लोगों को जागृत किया वरन संपूर्ण विश्व में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का लोहा मनवाया। इसी क्रम मे 11 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म संसद में भारत के हिंदुत्व, आध्यात्मिकता व भारतीय दर्शन पर दिया गया उनका भाषण ऐतिहासिक महत्व रखता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिकागो भाषण में गर्व से कहा था कि ५मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने विश्व भर को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया।५ उन्होंने कहा था कि हमारी सभ्यता लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने वाली रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने साम्प्रदायिकता को धर्म व सभ्यता का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। डा. श्रीप्रकाश मिश्र ने कहा जिस समय स्वामी जी ने भारतीय संस्कृति को विश्व भर में प्रतिष्ठित किया उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। पराधीनता की बेड़ियों मे फंसा हुआ हमारा देश गुलामी के साथ साथ सामाजिक रूढ़ियों और पुरातनपंथी परंपराओं मे भी बद्ध था। इसी समय स्वामी विवेकानंद ने अपने समर्थ गुरु रामकृष्ण परमहंस के मार्गदर्शन में अपनी आध्यात्मिक चेतना विकसित की और दिशाहीन भारतीय समाज को धर्म व संस्कृति के सही व सटीक पहलुओं से अवगत कराया। ऐसे समय मे जब ईसाई धर्मांतरण तीव्र गति से फैल रहा था , स्वामी जी ने प्रत्येक भारतवासी के हृदय में अपने धर्म और संस्कृति के प्रति सम्मान जागृत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने धर्म को रूढ़ियों से मुक्त कर सहज सरल जीवन शैली के रूप मे स्थापित किया जिसका मूल तत्व सेवाभाव और आत्मीयता थे। डा. श्रीप्रकाश मिश्र ने कहा स्वामी विवेकानंद ने अपनी जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और कर्मयोग को युवाओ के लिए एक आदर्श के रूप मे स्थापित किया। विभिन्न पूजा पद्धतियों, कर्मकांडों, अनुष्ठानों इत्यादि के ऊपर उन्होंने एक मात्र धर्म सेवा को स्थान दिया। भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रसार तथा भारत में आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना के पुनर्जागरण के लिए देश सदैव उनका ऋणी रहेगा। उनकी गुरु भक्ति , सांस्कृतिक चेतना और देशप्रेम आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत है। कार्यक्रम में मातृभूमि शिक्षा मंदिर के बच्चों को परितोषिक भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में आश्रम के सदस्य, विद्यार्थी, शिक्षक आदि उपस्थित रहे।

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 11वां भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन बेंगलुरु में शुरू

मनदीप कौर

चंडीगढ़, ८ राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) का 11वां भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन वीरवार को बेंगलुरु में शुरू हो गया। सम्मेलन में देश भर के विधान मंडलों के पीठासीन अधिकारी शिरकत कर रहे हैं। इसमें सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। हरियाणा का प्रतिनिधित्व विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण और उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा कर रहे हैं। वीरवार को बेंगलुरु पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

सम्मेलन के पहले दिन लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में एग्जिक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण भी शामिल हुए। इस दौरान सम्मेलन की कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके बाद सम्मेलन का उद्घाटन सत्र हुआ। इस दौरान लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुग्राम में आयोजित शहरी स्थानीय निकायों के सम्मेलन की सफलता के लिए हरियाणा विधान सभा और प्रदेश सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन देश में अपने आप में पहला विशिष्ट प्रयोग था, जो हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण के प्रयासों से सफलतापूर्वक सिरे चढ़ सका। इस चर्चा के दौरान हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने सुझाव दिया कि पहली बार चुनकर आने वाले मंत्रियों के लिए भी प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे उनको संसदीय कामकाज की बारीकियों से अवगत करवाया जा सके। विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने हरियाणा विधान सभा की ओर से चंडीगढ़ में मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित कार्यशाला का भी जिक्र किया। सम्मेलन में इसकी सराहना की गई। सम्मेलन में दल–बदल निरोधक कानून की समीक्षा समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ाए जाने का भी सुझाव आया। कहा गया कि इस समिति में 4 सदस्य होते हैं, लेकिन अब इनकी संख्या 10 से 12 की जानी चाहिए। सम्मेलन 13 सितंबर तक चलेगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के 11वें भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण और उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर ने कोटला गाँव में सामुदायिक चर्चा का किया आयोजन

सोनू

जालंधर–राष्ट्रीय सांख्यिकी क्षेत्रीय कार्यालय जालंधर ने भोगपुर के कोटला गाँव में ५एनएसएस – गौरवशाली अतीत से लेकर एक विकसित भारत के लिए आशाजनक भविष्य तक५ विषय पर एक सामुदायिक चर्चा का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान, एनएसओ के अधिकारियों ने ग्रामीणों को एनएसएस द्वारा की जा रही गतिविधियों और सर्वेक्षणों के बारे में जानकारी दी और राष्ट्रीय विकास में नमूना सर्वेक्षणों के महत्व के बारे में जागरूक किया। इस कार्यक्रम में श्रीमती पल्लवी अग्रवाल श्रीवास्तव संयुक्त निदेशक, श्री हरबलास उप निदेशक, श्री अरुण कुमार सहायक निदेशक, श्री उमेश कुमार लिम्बु, श्रीमती मनीषा, श्री गौरव जैन, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ गणनाकार, पर्यवेक्षक और समुदाय के सदस्य जिनमें श्रीमती बलविंदर कौर, श्रीमती अमरजीत कौर, श्री सुखदेव राज, श्री संदीप सिंह, श्री रविंदर और सुश्री जैस्मीन उपस्थित थे।

भारत का आर्थिक मंथन और विकास का अमृत

हरदीप सिंह पुरी

लेखक केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं

भारतीय सभ्यता में अरसे से यह मान्यता रही है कि कामयाबी से पहले परीक्षा होती है। समुद्र मंथन, जहां मथने की प्रकिया से अ म ृ त निकला था, इसी तरह हमारे आर्थिक मंथन ने भी हमेशा ही नवीनता का मार्ग प्रशस्त किया है। वर्ष1991 के संकट से जहां उदारीकरण का जन्म हुआ; वहीं महामारी से डिजिटल उपयोग तेज हुआ। और आज, भारत को एक ५मृत अर्थव्यवस्था५ कहने वाले संशयवादियों के शोर–शराबे के बीच – तीव्र विकास, मजबूत बफर, और व्यापक अवसर – की एक तथ्यपरक कहानी उभर कर सामने आई है।

जीडीपी के ताजा आंकड़ों पर जरा गौर करें। वित्तीय वर्ष 2025–26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी। यह वृद्धि दर पिछली पांच तिमाहियों में सबसे अधिक है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वृद्धि व्यापक है- सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) 7.6 प्रतिशत बढ़ा है, जिसमें मैन्यूफैक्चरिंग 7.7 प्रतिशत, निर्माण 7.6 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र लगभग 9.3 प्रतिशत बढ़ा है। नॉमिनल जीडीपी में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह कोई मनमाने तरीके से बताई गई तेजी नहीं है। यह बढ़ते उपभोग, मजबूत निवेश और निरंतर सार्वजनिक पूंजीगत व्यय व पूरी अर्थव्यवस्था में लागत कम करने वाले लॉजिस्टिक्स संबंधी सुधारों से हासिल नतीजों का सबूत है।

भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और सबसे तेज गति से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यह तेजी के मामले में दुनिया की पहली और दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं क्रमश: अमेरिका और चीन से भी आगे निकल गई है। वर्तमान गति से, हम इस दशक के अंत तक जर्मनी को पीछे छोड़कर बाजार–विनिमय के संदर्भ में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर हैं। हमारी गति वैश्विक स्तर पर मायने रखती है। स्वतंत्र अनुमान बताते हैं कि भारत पहले से ही वैश्विक वृद्धि में 15 प्रतिशत से अधिक का योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री ने एक स्पष्ट लक्ष्य रखा है — सुधारों के मजबूत होने और नई क्षमताओं के सामने आने के साथ–साथ वैश्विक वृद्धि में हमारी हिस्सेदारी बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंचे।

विभिन्न बाजारों और रेटिंग एजेंसियों ने हमारे इस अनुशासन को मान्यता दी है। एसएंडपी ग्लोबल ने मजबूत विकास, मौद्रिक विश्वसनीयता और राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का हवाला देते हुए, 18 वर्षों में पहली बार भारत की 'सॉवरेन रेटिंग' को उन्नत किया है। इस अपग्रेड से उधार लेने की लागत कम होती है और निवेशक आधार का विस्तार होता है। यह ५मृत अर्थव्यवस्था५ की धारणा को भी झुठलाता है। जोखिम के स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं ने अपनी रेटिंग के साथ अपना मत दिया है।

उतना ही महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि आखिर इस सबका लाभ किसे मिला है। वर्ष 2013–14 और 2022–23 के बीच, 24.82 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकल आए हैं। यह बदलाव उन बुनियादी सेवाओं – बैंक खाते, रसोई के लिए स्वच्छ ईंधन, स्वास्थ्य बीमा, नल का जल और प्रत्यक्ष हस्तांतरण – की बड़े पैमाने पर आपूर्ति पर निर्भर है जो गरीबों को विकल्प चुनने का अधिकार देता है। दुनिया के सबसे जीवंत लोकतंत्र और उल्लेखनीय जनसांख्यिकीय चुनौतियों के बीच विकास का यह पैमाना बेहद खास है। विकास का भारत का यह मॉडल आम सहमति के निर्माण, प्रतिस्पर्धी संघवाद और डिजिटल माध्यमों के उपयोग से अंतिम छोर तक सेवा प्रदान करने को महत्व देता है। यह घोषणा के मामले में धीमा, क्रियान्वयन के मामले में तेज और निर्माण की दृष्टि से टिकाऊ है। जब आलोचक हमारी तुलना तेज भागने वाले सत्तावादियों से करते हैं, तो वे इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि हम मैराथन धावक की तर्ज पर लंबी दूरी तय करने वाली एक अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं।

भारत के पेट्रोलियम मंत्री के रूप में, मैं इस बात की पुष्टि कर सकता हूं कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा इस तीव्र विकास में किस प्रकार सहायक की भूमिका निभा रही है। आज, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता, चौथा सबसे बड़ा तेलशोधक (रिफाइनर) और एलएनजी का चौथा सबसे बड़ा आयातक है। हमारी तेलशोधन (रिफाइनिंग) क्षमता 5.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन से अधिक है और इस दशक के अंत तक इसे 400 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से आगे बढ़ाने का एक स्पष्ट रोडमैप हमारे पास उपलब्ध है।

भारत की ऊर्जा संबंधी मांग – जो 2047 तक दोगुनी होने का अनुमान है – बढ़ती वैश्विक मांग का लगभग एक–चौथाई हिस्सा होगी, जिससे हमारी सफलता वैश्विक ऊर्जा स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बन जाएगी। सरकार का दृष्टिकोण सुरक्षा को सुधार के साथ जोड़ने का रहा है। तेल की खोज का क्षेत्र 2021 में तलछटी घाटियों के 8 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 16 प्रतिशत से अधिक हो गया है। हमारा लक्ष्य 2030 तक इसे बढ़ाकर 10 लाख वर्ग किलोमीटर करना है। तथाकथित 'निषिद्ध' (नो–गो) क्षेत्रों में 99 प्रतिशत की भारी कमी ने अपार संभावनाओं को जन्म दिया है, जबकि ओपन एकरेज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। गैस मूल्य निर्धारण से संबंधी नए सुधारों – जिनमें कीमतों को भारतीय कच्चे तेल की टोकरी से जोड़ा गया है और गहरे पानी एवं नए कुओं के लिए 20 प्रतिशत प्रीमियम की पेशकश की गई है – ने निवेश को बढ़ावा दिया है।

हमारी ऊर्जा की कहानी सिर्फ हाइड्रोकार्बन की ही नहीं, बल्कि बदलाव की भी कहानी है। वर्ष 2014 में इथेनॉल मिश्रण 1.5 प्रतिशत से बढ़कर आज 1.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत के बराबर हो गई है और किसानों को सीधे एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान हुआ है। सतत के तहत 300 से ज़्यादा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य 2028 तक 5 प्रतिशत मिश्रण का है और तेल से जुड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हरित हाइड्रोजन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।

भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर कुछ जगहों में काफी शोरगुल हुआ है। आइए तथ्यों को इस शोरशराबे से अलग करके देखें। रूस की तेल पर ईरान या वेनेज़ुएला के कच्चे तेल की तरह कभी प्रतिबंध नहीं लगाया गया। यह जी7/ईयू मूल्य–सीमा प्रणाली के अंतर्गत है जिसे जानबूझकर राजस्व को सीमित रखते हुए तेल प्रवाह को बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे पैकेजों के 18 दौर हो चुके हैं और भारत ने हरेक दौर का पालन किया है। प्रत्येक लेनदेन में कानूनी लदान (शिपिंग) एवं बीमा, अनुपालन करने वाले व्यापारियों और लेखा–परीक्षण (ऑडिट) किए गए चैनलों का उपयोग किया गया है। हमने कोई नियम नहीं तोड़े हैं। हमने बाजारों को स्थिर किया है और वैश्विक कीमतों को बढ़ने से रोका है।

कुछ आलोचकों का आरोप है कि भारत रूस के तेल के लिए एक ५लौंड्रोमैट५ बन गया है। इससे अधिक निराधार बात और कुछ नहीं हो सकती। भारत इस संघर्ष से काफी पहले दशकों से पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक रहा है और हमारे रिफाइनर विश्व भर से इस प्रकार के क्रूड का एक समूह बनाते हैं। निर्यात आपूर्ति श्रृंखलाओं को सक्रिय रखता है। वास्तव में, रूस के कच्चे तेल पर प्रतिबंध लगाने के बाद यूरोप ने भी भारतीय ईंधनों की ओर रुख किया। निर्यात की मात्रा और रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) मोटे तौर पर समान ही हैं। मुनाफे लेने का इसमें का कोई सवाल ही नहीं है।

यह तथ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि भारत ने यूक्रेन संघर्ष के बाद वैश्विक कीमतों में उछाल आने पर अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए निर्णायक रूप से कदम उठाए। तेल से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) ने डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर तक के नुकसान को सहन किया। सरकार ने केन्द्रीय और राज्य के करों में कटौती की और निर्यात से जुड़े नियमों ने यह अनिवार्य किया कि विदेशों में पेट्रोल और डीजल बेचने वाले रिफाइनर को घरेलू बाजार में कम से कम 50 प्रतिशत पेट्रोल और 30 प्रतिशत डीजल बेचना होगा।

इन उपायों ने, काफी राजकोषीय लागत पर, यह सुनिश्चित किया कि एक भी खुदरा दुकान खाली न रहे और परिणामस्वरूप भारतीय घरों के लिए कीमतें स्थिर रहीं। बड़ा सच यह है कि वैश्विक तेल का लगभग 10 प्रातशत आपूर्ति करने वाले दुनिया के इस दूसरे सबसे बड़े उत्पादक का कोई विकल्प ही नहीं है। जो लोग उंगली उठा रहे हैं, वे इस तथ्य की अनदेखी करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम के अपने सभ्यतागत मूल्यों के अनुरूप भारत द्वारा सभी अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करने से 200 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के विनाशकारी झटके को रोका गया।

यह वही %मेड इन इंडिया% है जो विश्व दृष्टिकोण के लिए भारत में आकार ले रही नई औद्योगिक क्रांति को आकार देता है। इस औद्योगिक क्रांति में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और विशेष रसायन शामिल हैं – जो उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों (पीएलआई) और पीएम गतिशक्ति लॉजिस्टिक्स के सहारे संचालित हैं। सेमीकंडक्टर के उत्पादन में तेजी अब एक नए स्तर पर पहुंच रही है – जो नीतिगत गंभीरता और क्रियान्वयन का प्रमाण है। मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत चार अतिरिक्त सेमीकंडक्टर मैन्यूफैक्चरिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है और प्रधानमंत्री का जापान में एक सेमीकंडक्टर उत्पादन केन्द्र का हालिया दौरा और जापान की निवेश संबंधी नवीनीकृत प्रतिबद्धताएं एक सुदृढ़ एवं विश्वसनीय तकनीकी आपूर्ति श्रृंखलाओं से संबंधित एक साझा रोडमैप को रेखांकित करती हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था इन लाभों को कई गुना बढ़ा देती है। भारत वास्तविक समय में भुगतान के मामले में दुनिया भर में अग्रणी है। यूपीआई की सर्वव्यापकता छोटे व्यवसायों की उत्पादकता बढ़ाती है और हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम नवाचार को सेवाओं एवं समाधानों के निर्यात में बदल रहा है। जब डिजिटल तेजी वास्तविक बुनियादी ढांचे के साथ मिलती है, तो प्रभाव बढ़ता है और परिणाम स्वरूप कम टकराव, सुव्यवस्थित और निवेश एवं उपभोग का एक बेहतर चक्र सुनिश्चित होता है।

आगे का रास्ता आशाजनक है। स्वतंत्र अनुमानों (ईवाई) के अनुसार, 2038 तक भारत पीपीपी के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 34 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होगा। यह प्रगति सतत सुधारों, मानव पूंजी और प्रत्येक उद्यम व परिवार के लिए प्रचुर, स्वच्छ एवं विश्वसनीय ऊर्जा पर निर्भर है।

एक महान सभ्यता की परीक्षा उसके कठिन क्षणों में होती है। अतीत में जब भी भारत की क्षमता पर संदेह किया गया, इस देश ने हरित क्रांतियों, आईटी क्रांतियों और शिक्षा व उद्यम के जरिए लाखों लोगों के गौरवपूर्ण उत्थान के साथ उसका जवाब दिया। आज का समय भी इससे कुछ अलग नहीं है। हम अपने दृष्टिकोण पर टिके रहेंगे, अपने सुधारों को निरंतर जारी रखेंगे और अपने विकास को तीव्र, लोकतांत्रिक एवं समावेशी बनाए रखेंगे ताकि लाभ सबसे वंचित लोगों तक पहुंच सके। आलोचकों के लिए, हमारी उपलब्धियां ही हमारा जवाब होंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, विकसित भारत महज एक आकांक्षा ही नहीं, बल्कि उपलब्धि का एक सार है और विकास के ये आंकड़े उस व्यापक कहानी का ताजा अध्याय मात्र हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया

रविंदर कुमार

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 9 सितंबर 2025 को पंजाब कादौरा किया और पंजाब के प्रभावित इलाकों में बादल फटनेऔर भारी बारिश से आई बाढ़ की स्थिति और उससे हुएनुकसान की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाईसर्वेक्षण किया। इसके बाद, उन्होंने गुरदासपुर

प्रधानमंत्री ने गुरदासपुर में बैठक में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की और नुकसान आकलन किया

मेंअधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ एकआधिकारिक समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने राहतऔर पुनर्वास उपायों की समीक्षा की और पंजाब में बाढ़ सेहुए नुकसान का आकलन भी किया। प्रधानमंत्री ने राज्य आपदा राहत कोष में पहले से मौजूद12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।एसडीआरएफ और पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरीकिस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की सहायता केलिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता परबल दिया। इसमें पीएम आवास योजना के अंतर्गत घरों कापुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों कापुनर्निर्माण, पीएमएनआरएफ के माध्यम से राहत प्रदानकरना और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करना जैसेउपाय शामिल होंगे। कृषि समुदाय को सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्णआवश्यकता को समझते हुए, विशेष रूप से उन किसानोंको अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पासवर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं हैं। जिन बोरवेल में गादभर गई है या जो बह गए हैं, उनके नवीनीकरण के लिएराज्य सरकार के विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार, राष्ट्रीय कृषिविकास योजना के अंतर्गत परियोजना आधार पर सहायताप्रदान की जाएगी। डीज़ल से चलने वाले बोरवेल के लिए, सौर पैनलों के लिएएमएनआरई के साथ अनुकूलन और प्रति बूंद अधिकफसल दिशानिर्देशों के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के लिएसहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण के अंतर्गत, ग्रामीणक्षेत्रों में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए पात्र परिवारों को घरोंके पुनर्निर्माण के लिए पंजाब सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेषपरियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए सरकारीस्कूलों को समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीयसहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार को दिशानिर्देशोंके अनुसार सभी आवश्यक सहायक जानकारी प्रदान करनीहोगी। जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब मेंजल संचयन हेतु पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण बड़े पैमानेपर किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्षतिग्रस्त पुनर्भरणसंरचनाओं की मरम्मत और अतिरिक्त जल संचयनसंरचनाओं का निर्माण करना होगा। इन प्रयासों से वर्षाजल संचयन में वृद्धि होगी और दीर्घकालिक जल स्थिरतासुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार ने नुकसान की सीमा का आकलन करने केलिए पंजाब का दौरा करने के लिए अंतर–मंत्रालयी केंद्रीयदल भी भेजे हैं, और उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार परआगे की सहायता पर विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों केपरिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की।

मोहिंदर भगत द्वारा राजस्व अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों को तुरंत मुआवज़ा पहुँचाने के निर्देश

पंकज

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी अगुवाई में, पंजाब सरकार इस प्राकृतिक आपदा का दृढ़ता से सामना करते हुए बाढ़ प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता प्रदान करने के लिए दिन–रात अथक मेहनत कर रही है। बारिश घटने और पानी का स्तर गिरने के साथ, राज्य सरकार ने राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण उपायों को और तेज कर दिया है, जिससे बाढ़ पीड़ितों की ज़िंदगी पुन: पटरी पर आने लगी है। कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि हलका श्री आनंदपुर साहिब के बाढ़ प्रभावित गांवों में 100 प्रतिशत सड़क संपर्क, बिजली तथा पानी की सप्लाई पुन: बहाल कर दी गई है। सिंहपुर–पलासी के निवासी अब राहत कैंपों से घर लौटने लगे हैं। मंत्री ने कहा कि हरसा बेला, पत्ती दूलची और बेला शिव सिंह जैसे कटे गांवों का संपर्क पुन: जोड़ा जा रहा है तथा बेला ध्यानी का टूटा लकड़ी का पुल अब मजबूत मोटरयुक्त पुल में बदला जाएगा।

पीएम नरेंद्र मोदी से मिले पूर्व सांसद सुशील रिंकू, वित्तीय सहायता प्रदान करने पर जताया आभार

बाढ़ की त्रासदी से गुजर रहे पंजाब को केंद्र सरकार हर संभव मदद के लिए वचनबद्ध – सुशील रिंकू

रमन कुमार

जालंधर, पंजाब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने पंजाब को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में सदी की सबसे बड़ी बाढ़ आपदा आई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। विपत्ति की इस घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी न केवल पंजाब के बाढ़ पीड़ितों से मिले, बल्कि आर्थिक सहायता की घोषणा भी की। पूर्व सांसद सुशील रिंकू ने कहा कि पंजाब के दौरे के दौरान उन्होंने गुरदासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात

की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विकट विपत्ति के समय हर व्यक्ति के साथ खड़े हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि – ऐसे समय में यह नहीं सोचना चाहिए कि कोई हाल पूछने या हाथ पकड़ने वाला नहीं है। केंद्र सरकार आपके साथ खड़ी है। सुशील रिंकू ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार पंजाब विकास के लिए हरसंभव मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सहायता का जो ऐलान किया है, उससे लोग शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोगों के हित और बेहतरी के लिए केंद्र सरकार हमेशा खड़ी है।

विधायी संवाद को नई दिशा देगा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का 11वां भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन - हरविन्द्र कल्याण

मनदीप कौर

चंडीगढ़, प्रमोद कौशिक 10 सितंबर - बेंगलुरु में 11 से 13 सितंबर तक होने जा रहा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (सीपीए) के 11वें भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए हरियाणा विधान सभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण बेंगलुरु पहुंच गए हैं। उनके साथ विधान सभा उपाध्यक्ष डॉ. कृष्ण लाल मिड्ढा, सचिव राजीव प्रसाद और अन्य अधिकारीगण भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। लोकतंत्र के मूल स्वरूप को मजबूत करने की दिशा में आयोजित इस सम्मेलन का विषय 'विधायी संस्थाओं में संवाद और चर्चा - जन विश्वास का आधार, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम' तय किया गया है। राष्ट्रमंडल भारतीय क्षेत्र का गठन 2004 में हुआ था। इससे पहले भारत राष्ट्रमंडल संसदीय संघ एशिया का हिस्सा था। भारतीय संसद के अतिरिक्त देश के 31 विधान मंडल इसके सदस्य हैं। विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने कहा कि आज जब लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं रह गया है और ऐसे में विधायिकाओं की भूमिका महज कानून

बनाने तक सीमित न रहकर जन अपेक्षाओं की पूर्ति और नीतिगत संवाद की ओर अग्रसर हो रही है। यह सम्मेलन न सिर्फ विभिन्न विधान मंडलों के बीच संवाद का मंच प्रदान करेगा, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर भी व्यापक चिंतन और मंथन का अवसर देगा। उन्होंने कहा कि विधायिकाओं में संवाद और चर्चा की परंपरा को मजबूती देना, न केवल पारदर्शिता को बढ़ाता है, बल्कि यह जनविश्वास की पुनर्स्थापना में भी सहायक होता है। इस सम्मेलन के माध्यम से राज्यों के विधान मंडल एक–दूसरे के अनुभवों से सीख सकेंगे और संसदीय कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बना सकेंगे। गौरतलब है कि यह सम्मेलन ऐसे समय पर हो रहा है जब देश में विधायी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर व्यापक विमर्श जारी है। प्रतिनिधियों के बीच खुली चर्चा और विचारों का आदान–प्रदान निश्चित ही नीति निर्माण की दिशा में सार्थक पहल होगी। साथ ही, यह आयोजन संघीय ढांचे के तहत केंद्र और राज्यों की विधायिकाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का भी माध्यम बनेगा। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण विधायी नवाचार और संवाद को लेकर गंभीर हैं। वे चाहते हैं कि समय के साथ भारतीय लोकतंत्र में विधायिकाओं की भूमिका अधिक उत्तरदायी व पारदर्शी होनी चाहिए। वे इस दिशा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'एक राष्ट्र–एक विधान मंडल' की सोच के अंतर्गत सम्मेलन और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं।

पेक के एनएसएस और एनसीसी विद्यार्थियों ने 'तेरा ही तेरा मिशन' संग मिलकर बाढ़ प्रभावितों के लिए 1.05 लाख की मदद दी

एस. के. सक्सैना

चंडीगढ़–पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज (डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी), चंडीगढ़ की राष्ट्रीय सेवा योजना (ह्वस्स्) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (ह्वष्टष्ट) इकाई ने तेरा ही तेरा मिशन, चंडीगढ़ के सहयोग से बाढ़ राहत अभियान आयोजित किया।

तेरा ही तेरा मिशन, जिसकी स्थापना और नेतृत्व डॉ. एच. एस. सब्बरवाल कर रहे हैं, लंबे समय से मानव सेवा में समर्पित है। यह मिशन चंडीगढ़ क्षेत्र में नेत्र अस्पताल और सामान्य स्वास्थ्य अस्पताल भी संचालित करता है। इस पहल के तहत, ह्वस्स् और ह्वष्टष्ट के स्वयंसेवी विद्यार्थियों ने राशन किटें तैयार कीं जिनमें आटा, तेल, दालें, बिस्कुट, पैक्ड खाद्य सामग्री, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीजें, कंबल और कपड़े शामिल थे। इसके साथ ही, ?1,05,435/– की राशि–जो विद्यार्थियों, फैकल्टी, स्टाफ और क्लष्ट

परिसर के निवासियों के सहयोग से एकत्रित की गई–को तेरा ही तेरा मिशन की प्रतिनिधि सुश्री जसप्रीत कौर को सौंपा गया। यह योगदान डॉ. संदीप कौर, डॉ. रत्तन लाल, डॉ. मयंक गुप्ता और डॉ. मोहित कुमार द्वारा, डीन स्टूडेंट अफेयर्स, डॉ. डी. आर. प्रजापति के मार्गदर्शन में किया गया। यह पहल विद्यार्थियों और संकाय की सामाजिक जिम्मेदारी और संवेदनशीलता को दर्शाती है, जिसने ज़रूरत के समय समाज के लिए सार्थक योगदान दिया।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना देगी युवा शक्ति के सपनों को नई उड़ान

लेखक
डॉ. मनसुख मांडविया
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, भारत सरकार

भारत की विकास गाथा हमेशा से उसकी श्रम शक्ति द्वारा लिखी गई है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में करोड़ों श्रमिकों के समर्पण और क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, पिछले 11 वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014 में, भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने वैश्विक पटल पर अपने लिए एक उल्लेखनीय स्थान बनाया है और इसमें इसके मानव संसाधन की शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

इस सफलता की कहानी को बल देने वाला तथ्य यह है कि भारत के आर्थिक विकास के साथ–साथ रोजगार का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आरबीआई–केएलईएमएस के अनुसार, जहां 2004–2014 के बीच केवल 2.9 करोड़ रोजगार सृजित हुए थे, उसके बाद के दशक में 17 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए। औपचारिकीकरण में भी तेजी आई है, ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार पिछले सात वर्षों में लगभग आठ करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं।

भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में बढ़तोरी होना भी हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। 2015 में, केवल 19 प्रतिशत भारतीय कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते थे। 2025 तक, यह संख्या बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो चुकी है और 94 करोड़ लाभार्थी इसके दायरे में आए हैं, जिससे भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने वाला देश बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस उपलब्धि को वैश्विक स्तर पर कवरेज के सबसे तेज विस्तार में से एक माना है।

यह स्पष्ट है कि राष्ट्र का भविष्य न केवल जीडीपी वृद्धि की गति से, बल्कि हमारे द्वारा सृजित नौकरियों की गुणवत्ता, श्रमिकों को दी जाने वाली सुरक्षा और अपने युवाओं को प्रदान किए जाने वाले अवसरों से भी तय होगा। बढ़ते स्वचालन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कारण बनी अनिश्चितता की स्थिति, आपूर्ति–श्रृंखला में बदलाव और दुनिया भर में नौकरियों को आकार देने वाली कई अन्य कमजोरियों की वैश्विक पृष्ठभूमि में, भारत एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बिंदु पर खड़ा है।

हमारी 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश है जो हमारी अर्थव्यवस्था को गति दे देता है, जबकि पश्चिमी देशों में आबादी वृद्ध होती हो रही है। वर्षों से, भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश यानी इसकी युवा शक्ति को इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है। फिर भी, पिछली सरकारों के अधीन, इस क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया। अमृत काल में, जब हम 2047 तक एक विकसित भारत के विजन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हमारे सामने कार्य स्पष्ट है- हमें फसंभावनाफ से फसमृद्धिफ की ओर बढ़ना होगा।

इस पृष्ठभूमि में, रोजगार अब केवल एक आर्थिक संकेतक नहीं रह गया है; यह सम्मान, समानता और राष्ट्रीय शक्ति का आधार है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने युवाओं को रोजगार योग्य बनाएं, उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करें, उन्हें वित्तीय साक्षरता से लैस करें और यह सुनिश्चित करें कि वे एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित हों। तभी हमारा जनसांख्यिकीय लाभ वास्तव में एक स्थायी राष्ट्रीय लाभांश में परिवर्तित हो सकता है।

इसी चुनौती का समाधान करने और आकांक्षा व अवसर के बीच के अंतर को पाटने के लिए, 15 अगस्त को लाल क़िले की प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। शुरुआत में केंद्रीय बजट 2024–25 में प्रस्तुत और प्रधानमंत्री जी के अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में घोषित यह योजना पैमाने और डिजाइन, दोनों ही दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, यह भारत के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिससे 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इनमें से दो करोड़ लाभार्थी पहली बार नौकरी पाने वाले नियोक्ताओं को सहायता

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को इसकी संरचना ही अलग बनाती है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले पहले के कार्यक्रमों के विपरीत, यह योजना युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यम प्रतिस्पर्धात्मकता की दोहरी चुनौती का एक साथ समाधान करती है। भाग 'ए' के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों (दो किश्तों में 15,000 रुपए तक) और भाग 'बी' के तहत नियोक्ताओं को (प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए प्रति माह 3,000 रुपए तक) को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, यह श्रमिकों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करता है और साथ ही व्यवसायों के लिए नियुक्ति जोखिम को भी कम करता है।

इस योजना का औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा एकीकरण की दिशा में प्रोत्साहन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नए कर्मचारियों को पहले दिन से ही सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, एक औपचारिक, सुरक्षित और उत्पादक श्रम बाजार की ओर एक संरचनात्मक कदम है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन पर अतिरिक्त ध्यान, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और प्रयास है।

समावेशी और सतत विकास को गति देना

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, योजना–आधारित पहलों से हटकर एक व्यापक रोजगार प्रणाली की ओर बदलाव का संकेत देती है। यह पूर्व की पहलों से मिली सीख पर आधारित है, उत्पादन–आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई), राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और मेक इन इंडिया जैसी वर्तमान योजनाओं का पूरक है और प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यवस्था में काम की बदलती प्रकृति को पहचानती है।

श्रमिकों और नियोक्ताओं, दोनों को प्रोत्साहन देकर, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यह मान्यता देती है कि रोजगार सृजन एक साझा जिम्मेदारी है। भारत डिजिटल नवाचार को अपनाते हुए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यह योजना सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न छूटे – यहां तक कि सबसे छोटा उद्यम और कार्यबल में शामिल होने वाला सबसे नया व्यक्ति भी राष्ट्रीय विकास की यात्रा में भागीदार बने।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना- नए भारत की नींव

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक नीतिगत घोषणा से कहीं अधिक बढ़कर है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश को सार्वजनिक समृद्धि में बदलने की दिशा में एक ठोस कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, यह पहल विकसित भारत के विजन को साकार करने की नींव का हिस्सा है, जहां हर युवा को सार्थक रोजगार मिले, हर काम में सम्मान हो और हर युवा को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिले। रोजगार निर्माण सही मायने में राष्ट्र निर्माण है। इस पहल के साथ, मोदी सरकार अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है कि कोई भी आकांक्षा अधूरी नहीं रहेगी और कोई भी युवा अवसर से वंचित नहीं रहेगा। हम सब मिलकर भारत की युवा शक्ति को नई उड़ान दे रहे हैं और उनके माध्यम से, विकसित भारत के सपने को भी नई गति प्रदान कर रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने श्री सिद्ध बाबा सोढल मंदिर में माथा टेका

दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा भावना का केंद्र बताया

एस. के. सक्सैना

जालंधर, पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी और रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने आज चल रहे सोढल मेले के दौरान श्री सिद्ध बाबा सोढल मंदिर में माथा टेका। इस अवसर पर संबोधन करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि अटूट विश्वास और श्रद्धा के कारण हर साल लाखों श्रद्धालु मंदिर में नतमस्तक होने आते है। उन्होंने कहा कि बाबा सोढल जी अपने आशीर्वाद से लाखों श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी करते है। मेले के विश्वव्यापी महत्व पर जोर देते हुए कैबिनेट मंत्री भगत ने कहा कि दुनिया भर से श्रद्धालु यहां बाबा जी का आशीर्वाद लेने आते है। उन्होंने आगे बताया कि पंजाब सरकार द्वारा मेले को उचित ढंग से संचालित करने के लिए पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित किए गए है। उन्होंने कहा कि जहां स्वास्थ्य टीमें तैनात की गई है, वहीं पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था, मोबाइल शौचालय और सुरक्षा आदि प्रबंधों को सुनिश्चित किया गया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने सभी संगठनों का मेले को सफल बनाने के लिए धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी के महत्वपूर्ण सहयोग से मेले के दौरान शांतिपूर्ण धार्मिक समागम संभव हो सका। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता नितिन कोहली, दिनेश ढल्ल और राजविंदर कौर थियाड़ा ने भी मंदिर में माथा टेका। इस दौरान मंदिर प्रबंधक कमेटी ने आई हुई हस्तियों को सम्मानित किया और पंजाब सरकार द्वारा इस वार्षिक मेले को सफल बनाने के लिए किए व्यापक पुख्ता प्रबंधों के लिए धन्यवाद किया।

अंतरराष्ट्रीय जाट धर्मशाला की मासिक बैठक आयोजित

पंजाब के बाढ़ से प्रभावित लोगों के हर संभव सहायता करेगा जाट समाज–प्रधान डॉ. कृष्ण श्योकंद

कुरुक्षेत्र, प्रमोद कौशिक ः अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला में आज मासिक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें संस्था के सचिव हरिकेश सहारन जी ने एक महीने का आमदनी और खर्चा पेश किया जिसमें उपस्थित सभी सदस्यों ने धर्मशाला में हो रहे विकासात्मक कार्यों और प्रगतिशील योजनाओं की खुलकर सराहना की। बैठक में समाज और धर्मशाला के उत्थान हेतु अनेक सुझाव और विचार प्रस्तुत किए गए। कुछ विचार ऐसे भी सामने आए जिनका उद्देश्य समाज की सोच को ऊँचा उठाना और अधिकाधिक सेवा–कार्यों की दिशा में आगे बढ़ना है। इस अवसर पर संस्था के प्रधान डॉ. कृष्ण श्योकंद ने पंजाब और हरियाणा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करते हुए अपील की कि इस कठिन समय में हमें अपने पंजाब के भाइयों के साथ खडे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 卐उनकी पीड़ा हमारी पीड़ा है, और हमें उनके लिए अन्न, वस्त्र, औषधि तथा हर संभव सहयोग पहुँचाना होगा।卐 समिति और उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों ने इस विचार का समर्थन किया और दृढ़ संकल्प लिया कि वे बाढ़ पीड़ितों की सेवा में तन, मन और धन से सहयोग करेंगे बैठक में समिति के अथक परिश्रम, दूरदर्शी सोच और निष्ठा की भूरि–भूरि प्रशंसा की गई। साथ ही अद्वितीय मार्गदर्शन और सशक्त नेतृत्व को समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया गया। सभी ने एक स्वर में कहा कि कार्यकारणी के निर्णयों और दिशा–निर्देशों के साथ पूरा समाज कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। समिति ने यह भी आश्वस्त किया कि धर्मशाला में बेहतर अवसंरचना, शिक्षा, सुरक्षा, सामाजिक सहयोग और भंडारा जैसी सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। हम आप को विश्वास दिलाते है कि निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला पूरे देश की अन्य संस्थाओं के लिए एक प्रकाशस्तंभ और आदर्श बनकर उभरेगी इस मौके पर संस्था के उप प्रधान बन्नी सिंह ढूल, होशियार सिंह,नरेंद्र नैन,गंगाबिशन, रमेश मलिक,ऋषिपाल नैन, बलविन्द्र, कर्मबीर सरपंच, दरिया सिंह, पूर्व प्रधान सुरेंद्र, राजेंद्र हथीरा, एडवोकेट सुखदेव, जीतेन्द्र, पूर्व प्रधान सुभाष बारना, टेकचंद पूर्व सरपंच, ऋषिपाल अटहेडी,पूर्व सरपंच मिया सिंह,कुलदीप ढिल्लों, मा. राजपाल किरमच आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के प्रो. राजा सिंगला ने दिया नया जीवन - सेवानिवृत इंस्पेक्टर राजकुमार

करंट लगने के बाद दर्द से कराह रहे थे बीएसएफ से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर, दर्द निवारक दवाइयां खाने से भी नहीं मिला आराम, आयुष विवि में पंचकर्म चिकित्सा से मिली नई जिंदगी

कुरुक्षेत्र, प्रमोद कौशिक, संजीव कुमारी ः करंट लगने के बाद असहनीय दर्द से कराह रहे बीएसएफ सेवानिवृत्त से सब इंस्पेक्टर की जिंदगी आयुर्वेद ने दोबारा पटरी पर ला दी। सब इंस्पेक्टर दर्द से निजात पाने के लिए कई अस्पतालों में भटक चुके थे, लेकिन कहीं से भी राहत नहीं मिली। अंत में उन्होंने कुरुक्षेत्र स्थित श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय का रुख किया, यहां पंचकर्म विभाग के प्रो. राजा सिंगला की देखरेख में उपचार हुआ। 30 दिन तक चले पंचकर्म इलाज ने उन्हें फिर से स्वस्थ कर दिया है।

डॉ. राजा के मुताबिक, राजकुमार की एमआरआई रिपोर्ट में रु–2 से रु–5 तक डिस्क प्रोलैप्स हुई थी। रु–5 और स–1 लेवल पर वर्टीबरी की समस्या और ष्ठ–10, ष्ठ–11 लेवल पर सूजन थी। पंचकर्म थेरेपी के जरिए उनका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। अब राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ है। करंट से शुरू हुआ दर्दनाक सफर। दरअसल, करनाल जिले के गांव सिद्धपुर निवासी 59 वर्षीय बीएसएफ से सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर राजकुमार को 25 अप्रैल 2025 को राजकुमार को बिजली का करंट लगा। करंट उनके दोनों पैरों से निकला, जिसके बाद उनकी कमर और टांगों में भयंकर दर्द रहने लगा। कई अस्पतालों और डॉक्टरों से इलाज कराने के बावजूद दर्द में कोई आराम नहीं आया। हालत यह हो गई कि राजकुमार सोते भी दर्द में थे और आंख भी दर्द में खुलती थी। राजकुमार बताते हैं दर्द इतना असहनीय था कि मुझे दिन में दो–दो दर्द निवारक गोलियां खानी पड़ती थीं। इसके बावजूद भी राहत नहीं मिलती थी। धीरे–धीरे चलने–फिरने में भी मुश्किल आने लगी थी। आयुष विश्वविद्यालय बना संजीवनी। राजकुमार के एक जानकार ने उन्हें श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय के पंचकर्म विभाग के प्रोफेसर डॉ. राजा सिंगला से मिलने की सलाह दी। 4 अगस्त को राजकुमार विश्वविद्यालय पहुंचे और 30 दिन तक उन्हें अस्पताल में भर्ती कर उपचार दिया गया। डॉ. राजा सिंगला और उनकी टीम ने उन्हें कटी बस्ती, पत्र पोटली स्वेदन, मात्रा बस्ती समेत अन्य आयुर्वेदिक औषधियों से उपचार दिया। लगातार पंचकर्म और थेरेपी से राजकुमार की स्थिति में सुधार हुआ और अब वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। पिछले 15 दिनों से उन्होंने दवाइयां लेना भी बंद कर दिया है। राजकुमार का कहना है कि यहां के वैद्य भगवान का दूसरा रूप हैं। मैं कई जगह इलाज करा चुका था, लेकिन आराम नहीं मिला। आयुष विश्वविद्यालय ने मुझे नई जिंदगी दी है। मरीजों की सेवा करना हमारा ध्येय- प्रो. सिंगला पंचकर्म विभाग के प्रोफेसर एवं आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राजा सिंगला ने कहा कि मरीजों की सेवा करना ही हमारा ध्येय है। विवि के कुलपति प्रो.वैद्य करतार सिंह धीमान के मार्गदर्शन में हर रोगी को बेहतर सुविधाओं के साथ आयुर्वेदिक उपचार किया जा रहा है। यही कारण है कि यहां इलाज के बाद मरीज स्वस्थ होकर नई जिंदगी पा रहे हैं।

पतन से प्रगति तक-पीएम मोदी कैसे गढ़ रहे हैं नया शहरी भारत ?

लेखक
श्री हरदीप सिंह पुरी
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

रोम एक दिन में नहीं बना था, वैसे ही नया शहरी भारत भी एक दिन में नहीं बनेगा। लेकिन जब हम अपने शहरों से और अधिक की अपेक्षा करते हैं, तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हम पहले ही कितनी दूरी तय कर चुके हैं? आजादी के दशकों बाद तक, भारत के शहर एक उपेक्षित विचार थे। नेहरू की सोवियत शैली की केंद्रीकृत सोच ने हमें शास्त्री भवन और उद्योग भवन जैसे कंक्रीट के विशाल भवन दिए, जो 1990 के दशक तक ही ढहने लगे थे और सेवा के बजाय नौकरशाही के स्मारक बनकर रह गए।

2010 के दशक तक दिल्ली की हालत बहुत खराब थी। सड़कों पर गड्ढे थे, सरकारी इमारतें पुरानी, बदरंग और टपकती छतों वाली थीं और एनसीआर की बाहरी सड़कों पर हमेशा जाम लगा रहता था। एक्सप्रेसवे बहुत कम थे, मेट्रो कुछ ही शहरों तक सीमित थी और बुनियादी ढांचा तेजी से टूट–फूट का शिकार हो रहा था। दुनिया का नेतृत्व करने का सपना देखने वाले देश की राजधानी उपेक्षा और बदहाल स्थिति का प्रतीक बन चुकी थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात को बदल दिया। उन्होंने शहरों को बोझ नहीं माना, बल्कि उन्हें विकास के इंजन और राष्ट्रीय गर्व का प्रतीक बनाया। यह बदलाव आज हर जगह दिखाई देता है। सेंट्रल विस्टा के पुनर्निर्माण ने कर्तव्य पथ को जनता की जगह बना दिया, नई संसद को भविष्य के अनुरूप संस्थान में बदल दिया और कर्तव्य भवन को सुचारु प्रशासनिक केंद्र बना दिया। जहां पहले जर्जर हालत थी, वहां अब महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास दिखता है।

इस बदलाव का पैमाना आंकड़ों से समझा जा सकता है। 2004 से 2014 के बीच शहरी क्षेत्र में केंद्र सरकार का कुल निवेश लगभग 1.57 लाख करोड़ था। 2014 के बाद से यह 16 गुना बढ़कर लगभग 28.5 लाख करोड़ हो गया है। 2025–26 के बजट में ही आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय को 96,777 करोड़ दिए गए, जिसमें एक–तिहाई हिस्सा मेट्रो के लिए और एक–चौथाई आवास के लिए रखा गया। इतना बड़ा वित्तीय निवेश स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ और इससे अभूतपूर्व रूप से शहरी ढांचे का स्वरूप बदल रहा है।

भारत की व्यापक आर्थिक और डिजिटल प्रगति ने इस रफ्तार को और तेज कर दिया है। आज हम लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, जहां डिजिटल व्यवस्था रोजमर्रा की जिंदगी को चला रही है। यूपीआई ने अभी हाल ही में एक महीने में 20 अरब लेन–देन का आंकड़ा पार किया और हर महीने 24 लाख करोड़ से ज़्यादा के लेन–देन संभाल रहा है। अब 90 करोड़ से अधिक भारतीय इंटरनेट से जुड़े हुए हैं और 56 करोड़ जनधन खाते जैम त्रिमूर्ति (जनधन, आधार, मोबाइल) का आधार हैं, जिसके ज़रिये सब्सिडी सीधे और पारदर्शी रूप से दी जाती है। यह पैमाना, औपचारिकता और फिनटेक अपनाने का मॉडल पूरी तरह भारतीय है और इसका असर सबसे गहरा शहरी क्षेत्रों पर दिखाई देता है। मेट्रो क्रांति जमीन पर हुए बदलाव को सबसे अच्छी तरह दिखाती है। 2014 में भारत में सिर्फ़ 5 शहरों में लगभग 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन चल रही थी। आज यह बढ़कर 23 से अधिक शहरों में 1,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई है, जो हर दिन एक करोड़ से अधिक यात्रियों को ढोती है। पुणे, नागपुर, सूरत और आगरा जैसे शहरों में नए कॉरिडोर बन रहे हैं, जिससे सफ़र तेज़, सुरक्षित और प्रदूषण–रहित हो रहा है। यह सिर्फ़ लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि

इसमें लोगों का समय बचना, हवा का साफ़ होना और नागरिकों को करोड़ों घंटे की अतिरिक्त उत्पादकता मिलना शामिल है।

शहरी कनेक्टिविटी की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। एनसीआर के जाम से भरे इलाकों को नई बनी यूईआर–द्बद्ब (दिल्ली की तीसरी रिंग रोड) से राहत मिल रही है, जो एनएच–44, एनएच–9 और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़कर पुराने जाम के बिंदुओं को आसान बना रही है। भारत की पहली क्षेत्रीय तेज़ यातायात प्रणाली–दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस (नमो भारत)–पहले ही बड़े हिस्से पर चल रही है और पूरा संचालन जल्द ही शुरू होने वाला है, जिससे पूरा सफ़र एक घंटे से कम समय में तय होगा। ये तेज़ और एकीकृत परिवहन प्रणालियां नए भारत के लिए एक नई महानगरीय सोच को आकार दे रही हैं।

एक्सप्रेसवे अब शहरों के बीच की आवाजाही का नया चेहरा बन रहे हैं। दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु–मैसूरु एक्सप्रेसवे, दिल्ली– मेरठ एक्सेस–नियंत्रित कॉरिडोर और मुंबई कोस्टल रोड ने दूरी घटा दी है और बड़े वाहनों को शहर की गलियों से बाहर निकालकर हवा को साफ़ किया है। मुंबई में देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु अब टापू जैसे शहर को मुख्य भूमि से सीधे जोड़ता है। मुंबई–अहमदाबाद हाई–स्पीड रेल, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना, तेज़ी से आगे बढ़ रही है और पश्चिम भारत में विकास का नया केंद्र बनने जा रही है।

समावेशन भी हमेशा प्राथमिकता में रहा है। पीएम स्वनिधि योजना ने 68 लाख से ज़्यादा रेहड़ी–पटरी वालों को बिना गारंटी वाला कर्ज़ और डिजिटल सुविधा दी है, जिससे छोटे उद्यमियों को रोज़गार फिर से खड़ा करने और औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ने का मौका मिला है। पीएम आवास योजना (शहरी) के तहत 120 लाख से अधिक मकानों की मंजूरी दी गई, जिनमें से लगभग 94 लाख पूरे हो चुके हैं। लाखों परिवार, जो पहले झुग्गियों में रहते थे, अब सुरक्षित पक्के घरों में रह रहे हैं। ये केवल आंकड़े नहीं, बल्कि बदली हुई ज़िंदगियां और नयी उम्मीदें हैं।

ऊर्जा सुधार ने शहरी जीवन को और सुविधाजनक बनाया है। जहां पहले रसोई महंगे और अनिश्चित गैस सिलेंडर बुकिंग पर निर्भर थी, अब पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) आम होती जा रही है, जो अधिक सुरक्षित, साफ़ और सुविधाजनक है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन 2014 में सिर्फ़ 57 क्षेत्रों तक सीमित था, जो अब बढ़कर 300 से अधिक हो गया है। घरेलू पीएनजी कनेक्शन 25 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ से ऊपर पहुंच गए हैं, जबकि हज़ारों सीएनजी स्टेशन सार्वजनिक परिवहन को और स्वच्छ बना रहे हैं। अब लाखों शहरी घरों में नल घुमाकर ईंधन मिलना हकीकत बन चुका है।

भारत ने अब दुनिया की मेज़बानी करने का आत्मविश्वास हासिल कर लिया है। भारत मंडपम ने सफलतापूर्वक जी 20 नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित किया। यशोभूमि अब दुनिया के सबसे बड़े सम्मेलन परिसरों में शामिल है, जहां एक साथ हज़ारों प्रतिनिधियों का स्वागत किया जा सकता है। इंडिया एनर्जी वीक ने बेंगलुरु, गोवा और नई दिल्ली में दुनिया की ऊर्जा कंपनियों और विशेषज्ञों को आकर्षित किया, जिससे यह साबित हुआ कि हमारे शहर बड़े पैमाने पर और बेहतरीन ढंग से दुनिया की मेज़बानी कर सकते हैं। यह सब तब अकल्पनीय था जब हमारे नागरिक ढांचे की पहचान टूटे–फूटे हॉल और खस्ताहाल स्टेडियम हुआ करते थे।

परिवहन का आधुनिकीकरण बड़े पैमाने और तेज़ी से हो रहा है। 2014 में जहां सिर्फ़ 74 हवाईअड्डे चालू थे, आज वह संख्या बढ़कर लगभग 160 हो गई है। यह संभव हुआ है उड़ान योजना और लगातार निवेश की वजह से। वंदे भारत ट्रेनें अब 140 से अधिक रूटों पर चल रही हैं, जिससे अलग–अलग क्षेत्रों में यात्रा का समय काफी घटा है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1,300 से अधिक रेलवे स्टेशनों का नवीनीकरण किया जा रहा है, जिनमें से सौ से ज़्यादा का उद्घाटन हो चुका है। दिल्ली में विस्तारित टर्मिनल–1 ने आईजीआई हवाईअड्डे की क्षमता 10 करोड़ यात्रियों से अधिक कर दी है, जिससे हमारी राजधानी दुनिया के बड़े हवाई केंद्रों की सूची में शामिल हो गई है।

समझदारी भरी कर नीति ने उपभोक्ताओं और विकास दोनों को सहारा दिया है। हाल ही में हुई जीएसटी सुधार के तहत ज़्यादातर वस्तुओं और सेवाओं को 5त्न और 18त्न की दरों में रखा गया है। ऊंचे टैक्स सिर्फ़ कुछ नशे और विलासिता की चीज़ों पर ही लगाए गए हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों से लेकर कई घरेलू सामानों पर टैक्स घटा है, छोटे कार और दोपहिया वाहन अब कम जीएसटी पर मिलते हैं। कई दवाइयां और मेडिकल उपकरण भी सस्ते हो गए हैं। शहरी परिवारों के लिए इसका मतलब हैकि महीने के खर्च कम होना, खपत बढ़ना और निवेश व रोज़गार का सकारात्मक चक्र चलना।

मैंने लंबे समय तक एक राजनयिक के रूप में विदेशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और वहां मैंने देखा कि कैसे शहर किसी देश का चेहरा बन जाते हैं वियना की रिंगस्ट्रासे, न्यूयॉर्क की ऊंची इमारतें या पेरिस की चौड़ी सड़कें– ये सब राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का प्रतीक थीं। तब मुझे साफ़ समझ आया कि दुनिया की नज़रें सबसे पहले किसी देश के शहरों पर जाती हैं। यही विश्वास मेरे शहरी कार्य मंत्रालय के काम का आधार बना कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और हमारे दूसरे शहर एक उभरते भारत का आत्मविश्वास, आधुनिकता और आकांक्षाएं दिखाएं। जैसे मेरे राजनयिक करियर ने मुझे सिखाया कि भारत की छवि दुनिया में कैसे प्रस्तुत करनी है, वैसे ही मंत्री के रूप में मेरा काम रहा है कि हमारे शहर उस छवि के लायक बनें।

यह है बदलाव की यात्रा- आज़ादी के बाद की उपेक्षा से मोदी युग के आधुनिकीकरण तक। शास्त्री भवन की जर्जरता से कर्तव्य भवन की महत्वाकांक्षा तक। गड्ढों वाली सड़कों से एक्सप्रेसवे और हाई–स्पीड कॉरिडोर तक। धुएं से भरे रसोईघरों से पाइप्ड नेचुरल गैस तक। झुग्गियों से लाखों पक्के घरों तक। टूटे–फूटे हॉल से विश्वस्तरीय सम्मेलन केंद्रों तक। संकोच करती राजधानी से आत्मविश्वासी वैश्विक मेज़बान तक।

पाटलिपुत्र और नालंदा जैसे भारत के प्राचीन शहर कभी शहरी सभ्यता की उच्चता के प्रतीक थे। आज, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय शहर फिर उसी राह पर हैं, आधुनिक लेकिन मानवीय, महत्वाकांक्षी होते हुए भी समावेशी, वैश्विक दृष्टिकोण वाले होते हुए भी जड़ों और मूल्यों से जुड़े हुए। नया शहरी भारत एक दिन में नहीं बन रहा है, बल्कि यह हर दिन बन रहा है– ईंट दर ईंट, ट्रेन दर ट्रेन, घर दर घर। और यह पहले से ही करोड़ों लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है।

(लेखक केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं।)

पढ़ें भारत हर ख़बर सच के साथ
आज तक आमने-सामने
पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली एवं हरियाणा
Email : aajtakaamnesaamne.in@gmail.com
RNI No-Punhin2013/54688

अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद की तरफ से जिलाध्यक्ष कार्यकारिणी हेतु आवेदन आमंत्रित

चंडीगढ- [कैप्टन सुभाष चंद्र शर्मा, ब्यूरो चीफ]-अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद卐 रजि- के अन्तर्गत पंजाब के द्वारा तेइस जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। संगठन ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सुयोग्य, सक्रिय,ब्राह्मण समाज को सशक्तिकरण एवं उत्थान करने हेतु स्वैच्छिक ब्राह्मण बंधु इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया नियत प्रारूप में पूर्ण विवरण सहित निर्धारित तिथि 30/09/2025 तक पूरी करनी होगी। परिषद का उद्देश्य सामाजिक एकता, गुरूकुल शिक्षा और भारतीय सांस्कृतिक के साथ–साथ भगवान श्री परशुराम जी के सिद्धांतों को बढ़ावा देना और हर वर्ग का संरक्षण करना है। पंजाब प्रदेश के अध्यक्ष डा. परविंदर शर्मा जी का कहना है कि उक्त प्रक्रिया निष्पक्ष व पारदर्शी रहेगी। क्यों कि संगठन का मूल उद्देश्य सामाजिक विकास करना है जो ज्ञानमेव ही कर सकते हैं। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अधिक से अधिक सुपात्र ब्रह्मदेवों से आवेदन करने की अपील की है। आवेदन इ मेल आई डी parvindersharmavlx@gmail.com के माध्यम से शीघ्र प्रेषित कर सकते हैं।

एनआईटीटीआर चंडीगढ़ ने 58वां वार्षिक समारोह मनाया

राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए नवाचार और कौशल विकास का आह्वान किया

कैप्टन शुभाष चंदर

चंडीगढ़,राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर), चंडीगढ़ (सम विश्विद्यालय , विशिष्ट श्रेणी, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) का 58वाँ वार्षिक दिवस समारोह 7 सितंबर, 2025 को आयोजित किया गया। समारोह की शुरुआत उत्तर भारत के राज्यों में बाढ़ से उत्पन्न भयावह स्थिति पर शोक एवं चिंता व्यक्त करने तथा प्रभावित नागरिकों के प्रति संस्थान द्वारा सहनुभूति प्रकट करने हेतु दो मिनट का मौन धारण किया गया। वार्षिक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के निदेशक प्रो. हीरालाल मुरलीधर सूर्यवंशी जी की उपस्थिति ने शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए, प्रो. सूर्यवंशी ने अंत:विषयक गतिविधियों के माध्यम से छात्रों और शिक्षार्थियों के समग्र विकास के महत्व पर बल दिया। उन्होंने छात्रों एवं शिक्षार्थियों को अपने सुविधा क्षेत्र से बाहर निकल कर शैक्षणिक यात्रा के विभिन्न शैक्षिक एवं पाठ्येतर अनुभवों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करके तकनीकी शिक्षा में निरंतर सुधार व अनुसंधान को आगे बढ़ाने और उत्कृष्टता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए एनआईटीटीआर, चंडीगढ़ को बधाई दी। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा सरकार के मुख्य अभियंता डॉ. सतबीर सिंह कादियान, समारोह के सम्मानित अतिथि थे। उन्होंने राष्ट्र द्वारा अभिज्ञात एक बड़ी आबादी को रोज़गार प्रदान करने की जनसांख्यिकीय चुनौती पर प्रकाश डाला और तकनीकी संस्थानों से शिक्षार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करके इसका समाधान प्रस्तुत करने का आह्वान किया। उन्होंने संस्थानों से आज राष्ट्र के सामने मौजूद बाढ़ जैसी विकट समस्याओं से उबरने के लिए नवीन समाधानों को प्रस्तुत करने का भी आग्रह किया। समारोह के दौरान संस्थान के मेधावी स्नातकोत्तर छात्रों और राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट पॉलिटेक्निक एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालयों को उनके अनुकरणीय समर्पण, दृढ़ता और उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया। संस्थान के कर्मचारियों को भी उनके विशेष योगदान, प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए सम्मानित किया गया। एनआईटीटीआर, चंडीगढ़ के निदेशक प्रो. (डॉ.) भोला राम गुर्जर द्वारा संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें संस्थान की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया, जो तकनीकी शिक्षकों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा तकनीकी कर्मचारियों के कौशल विकास में उत्कृष्टता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संस्थान द्वारा कार्यरत पेशेवरों हेतु अपने आगामी बी.टेक. कार्यक्रम की भी घोषणा की गई। संस्थान के वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर, 卐राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अंतर्गत पॉलिटेक्निक शिक्षा में अवसर और चुनौतियाँ卐 विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का भी उद्घाटन किया गया। इस सम्मेलन में देश भर के 60 पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के प्रशासक, प्राचार्य एवं संकाय सदस्य भाग लेंगे व एनईपी 2020 के आलोक में पॉलिटेक्निक शिक्षा प्रणाली को नया रूप देने पर विचार–विमर्श करेंगे।

पुलिस कमिश्नर द्वारा विभिन्न प्रतिबंधों के आदेश जारी

मनदीप कौर

जालंधर, पुलिस कमिश्नर जालंधर धनप्रीत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का हथियार जैसे बेसबॉल, तेज हथियार, नुकीला हथियार या कोई भी जानलेवा हथियार गाड़ी में रखकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, कमिश्नरेट पुलिस की सीमा में

मैरिज पैलेस/होटलों के बैंक्वेट हॉल, शादी–विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में हथियार ले जाने पर प्रतिबंध

किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, किसी समारोह/जुलूस में हथियार लेकर चलने, पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और नारेबाजी करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस कमिश्नर द्वारा एक अन्य आदेश के माध्यम से कमिश्नरेट पुलिस की सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी मैरिज पैलेस/होटलों के बैंक्वेट हॉल, शादी–विवाह के कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में लोगों द्वारा हथियार ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मैरिज पैलेस और बैंक्वेट हॉल के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जिम्मेदार होंगे। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, मकान मालिक अपने घरों में किरायेदारों को, पीजी मालिक अपने पीजी में, और आम लोग अपने घरों में नौकरों या अन्य कर्मचारियों को बिना अपने नजदीकी पंजाब पुलिस के साझा केंद्र में जानकारी दिए नहीं रखेंगे। एक अन्य आदेश के तहत, पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में सभी पटाखों के निर्माताओं/डीलरों को निर्देश दिया गया है कि पटाखों के पैकेटों पर ध्वनि का स्तर (डेसिबल में) प्रिंट करना अनिवार्य होगा। पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी एक अन्य आदेश के अनुसार, कोई भी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय का मालिक/प्रबंधक किसी भी व्यक्ति/यात्री को उसकी पहचान सत्यापित किए बिना नहीं ठहराएगा। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री का वैध फोटो पहचान पत्र, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, उस व्यक्ति/यात्री द्वारा स्व–प्रमाणित फोटोकॉपी के रूप में रिकॉर्ड के लिए रखा जाएगा। साथ ही, व्यक्ति/यात्री का मोबाइल नंबर सत्यापित करने के अलावा, ठहरने वाले व्यक्ति/यात्री का रिकॉर्ड दिए गए प्रोफार्मा में रजिस्टर पर मेंटेन किया जाएगा। होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय में ठहरे व्यक्तियों/यात्रियों से संबंधित जानकारी प्रतिदिन सुबह 10 बजे संबंधित थाना प्रभारी को भेजी जाएगी, और ठहरे व्यक्तियों/यात्रियों से संबंधित रजिस्टर में दर्ज रिकॉर्ड को प्रत्येक सोमवार को संबंधित थाना प्रभारी से सत्यापित करवाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर यह रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके अलावा, जब भी कोई विदेशी व्यक्ति किसी होटल/मोटल/गेस्ट हाउस या सराय में ठहरता है, तो इसकी सूचना तुरंत प्रभारी विदेशी पंजीकरण कार्यालय, पुलिस कमिश्नर कार्यालय, जालंधर को दी जाएगी। साथ ही, प्रत्येक होटल/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय के गलियारों, लिफ्ट, रिसेप्शन काउंटर और मुख्य प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल/मोटल/गेस्ट हाउस, रेस्तरां या सराय में ठहरता/आता है, जो किसी पुलिस मामले में वांछित है, या किसी अन्य राज्य/जिले की पुलिस द्वारा किसी होटल/रेस्तरां/मोटल/ गेस्ट हाउस या सराय में ठहरे/आए व्यक्ति/यात्री को गिरफ्तार किया जाता है, तो होटल/रेस्तरां/मोटल/गेस्ट हाउस और सराय का मालिक/प्रबंधक तुरंत इसकी सूचना संबंधित थाने/पुलिस कंट्रोल रूम को देने के लिए जिम्मेदार होगा।

गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का साथी पांच पिस्तौलों सहित काबू

गोल्डी बराड़ के निर्देशों पर उसके मुख्य सहयोगी मलकियत सिंह उर्फ़ किट्टा भानी के ज़रिये खरीदे गए थे हथियार–डीजीपी गौरव यादव

पंकज

चंडीगढ़, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के तहत पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए चल रहे अभियान के दौरान संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता दर्ज करते हुए पंजाब पुलिस की गैंगस्टर विरोधी टास्क फोर्स (एजीटीएफ) ने विदेश आधारित गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के एक साथी को पांच .32 बोर पिस्तौलों सहित 10 जिंदा कारतूसों सहित गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने रविवार को यहां दी। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान बलजिंदर सिंह उर्फ़ रैंच निवासी माही नंगल, जिला बठिंडा के रूप में हुई है। आरोपी की आपराधिक पृष्टभूमि है और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति सरहदी राज्य में शांति और सद्भावना भंग करने के लिए गोल्डी बराड़ गैंग को अवैध हथियारों की सप्लाई करता था। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये हथियार गोल्डी बराड़ के निर्देशों पर उसके मुख्य सहयोगी मलकियत सिंह उर्फ़ किट्टा

भानी (जो इस समय कपूरथला जेल में बंद है) के ज़रिये खरीदे गए थे। डीजीपी ने कहा कि इस मामले में अगले–पिछले संबंध स्थापित करने और पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए और जांच जारी है। ऑपरेशन के विवरण साझा करते हुए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एजीटीएफ पंजाब प्रमोद बान ने बताया कि डीएसपी एजीटीएफ बठिंडा रेंज जसपाल सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस टीमों को गोल्डी बराड़ गैंग द्वारा राज्य में सनसनीखेज अपराध की साज़िश रचने की पुख़्ता जानकारी मिली थी। उन्होंने कहा कि तेजी से कार्रवाई करते हुए एजीटीएफ पंजाब की टीमों ने संदिग्ध बलजिंदर रैंच को मलोट, श्री मुक्तसर साहिब में मलोट–मुक्तसर सड़क, न्यू बाईपास स्थित फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे से सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया।

शिक्षा मंत्री द्वारा सभी शैक्षणिक संस्थानों को पुन: खोलने की घोषणा

रमन कुमार

चंडीगढ़, प्रदेश में हाल ही में आई भयंकर बाढ़ और भारी बारिशों के बाद हालात पहले की तरह हो रहे हैं, इसको देखते हुये पंजाब के शिक्षा मंत्री श्री हरजोत सिंह बैंस ने आज प्रदेश के सभी स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, पॉलिटेक्निक संस्थानों और आई.टी.आई. सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को 8 सितंबर से पुन: खोलने की घोषणा की है। साथ ही गंभीर रूप से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में इन संस्थानों को बंद रखने संबंधी फ़ैसला लेने का अधिकार डिप्टी कमिश्नरों को दिया गया है। इन संस्थानों को पुन: खोलने की योजना के बारे में विस्तार से बताते हुए श्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि निजी स्कूल 8 सितंबर को शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए पुन: खुलेंगे। इसके साथ ही भवन और कक्षाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना स्कूल प्रबंधन की ज़िम्मेदारी होगी। सरकारी स्कूलों की समय–सारणी अलग होगी- शिक्षक और स्टाफ़ 8 सितंबर को निरीक्षण, सफ़ाई और नुक़सान का जायज़ा लेकर रिपोर्ट करेंगे तथा विद्यार्थियों की कक्षाएँ 9 सितंबर से दोबारा शुरू होंगी। उन्होंने स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया कि वे एस.एम.सीज़., पंचायतों और नगर परिषदों की मदद से सरकारी स्कूलों की सफ़ाई सुनिश्चित करें और यदि इमारत या क्लासरूम को कोई नुक़सान हुआ है तो इसकी रिपोर्ट तुरंत डिप्टी कमिश्नर, एस.डी.एम. या इंजीनियरिंग विभाग को दें, ताकि विद्यार्थियों और स्टाफ़ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सरकारी स्कूल सोमवार को खुलेंगे लेकिन कक्षाएँ मंगलवार से शुरू होंगी, डिप्टी कमिश्नरो को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों को लेकर फ़ैसला लेने के अधिकार दिये

शिक्षा के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण–सावित्री बाई फुले की विरासत

लेखिका
श्रीमती सावित्री ठाकुर, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार

शिक्षक दिवस उन महान व्यक्तित्वों को सम्मानित करने का अवसर है, जो अपने ज्ञान और मार्गदर्शन से राष्ट्र का भविष्य संवारते हैं। इस दिन हम भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले (1831–1897) को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, जिन्होंने हमारे देश में महिला शिक्षा की नींव रखने के लिए पुराने सामाजिक पूर्वाग्रहों को साहसपूर्वक चुनौती दी थी।

ऐसे दौर में जब महिलाओं की शिक्षा को नापसंद किया जाता था और अक्सर हिंसक तरीके से इसका विरोध किया जाता था, सावित्रीबाई फुले ने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उन्होंने केवल पढ़ाया ही नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम भी तैयार किए और महिलाओं को ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करने हेतु कविताएँ भी लिखीं। उनका जीवन साहस का प्रमाण था—वह रोज़ाना एक अतिरिक्त साड़ी के साथ स्कूल जाती थीं, क्योंकि रूढ़िवादी पुरुष उन पर कीचड़ और पत्थर फेंकते थे। फिर भी वह डटी रहीं, क्योंकि वह जानती थीं कि भारत का भविष्य उसकी बेटियों की शिक्षा में निहित है।

सुधारकों की विरासत और समानता का आह्वान

सावित्रीबाई फुले अपने संघर्ष में अकेली नहीं थीं। भारत के समाज सुधार की यात्रा को राजा राम मोहन राय जैसे महान व्यक्तित्वों ने दिशा दी, जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई और महिला शिक्षा का समर्थन किया। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह और बालिका शिक्षा की वकालत की। आगे चलकर महात्मा गांधी ने भी इस बात पर ज़ोर दिया कि 'महिलाओं की शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली माध्यम है।' इन सभी सुधारकों का मानना था कि जब तक महिलाएँ शिक्षा से सशक्त नहीं होंगी, भारत को सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता नहीं मिल सकती।

यह विरासत आज भी आधुनिक भारत की आकांक्षाओं को दिशा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अक्सर इस बात पर ज़ोर दिया है कि भारत की विकास यात्रा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास से आगे बढ़ेगी।

'विकसित भारतश्च2047' का विज़न भी इसी सोच पर आधारित है, जिसमें महिलाओं को राष्ट्र निर्माण का समान भागीदार बनाया गया है, और इस सशक्तिकरण की नींव शिक्षा है।

महिलाएँ और शिक्षा- अब तक की प्रगति

स्वतंत्रता के बाद से इस दिशा में हुई प्रगति उल्लेखनीय रही है। महिला साक्षरता, जो 1951 में मुश्किल से 8.86 प्रतिशत थी, आज बढ़कर 65.46 प्रतिशत (2011 की जनगणना के अनुसार) हो चुकी है और हाल के सर्वेक्षणों से स्कूलों में लड़कियों के बढ़ते नामांकन यह इंगित करते हैं कि इसमें लगातार सुधार हो रहा है।एकीकृत जिला शिक्षा सूचनाप्रणाली (यूडीआईएसई+) 2021–22 के अनुसार, प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) अब लड़कों की तुलना में अधिक है।

मोदी सरकार ने 2015 में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना शुरू की, जिसने समाज की सोच बदली, बाल लिंगानुपात में सुधार किया और स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर लड़कियों के नामांकन को बढ़ाया। पोषण अभियान, मिशन शक्ति और सामर्थ्य जैसी पहल मिलकर ऐसा ढांचा तैयार करती हैं, जिसमें शिक्षा को पोषण, सुरक्षा और अवसर का सहारा मिलता है। यूडीआईएसई+ 2024–25 के आँकड़े बताते हैं कि पहली बार भारत में महिला शिक्षकों की संख्या कुल स्कूली शिक्षकों का 54.2 प्रतिशत हो गई है, जो 2014–15 के 46.9 प्रतिशत से कहीं अधिक है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान कर दिया है।यह संस्थान महिलाओं और बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों को मज़बूत बनाने के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सुनिश्चित करता है कि नीतियाँ ज़मीनी स्तर पर प्रभावी रूप से क्रियान्वित हों। सावित्रीबाई फुले के नाम के साथ, यह संस्थान शिक्षा और सुधार के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के उनके विजन के प्रति जीवंत श्रद्धांजलि है।

फिर भी कुछ चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कम उम्र में विवाह, सुरक्षा की चिंता और आर्थिक कारणों से कई लड़कियाँ माध्यमिक स्तर पर पढ़ाई छोड़ देती हैं। सरकार इन चुनौतियों को दूर करने के लिए छात्रवृत्ति, आवासीय सुविधा, मासिक धर्म स्वच्छता पहल और डिजिटल शिक्षा के अवसर उपलब्ध करा रही है, ताकि हर लड़की बिना रुकावट अपनी पढ़ाई पूरी कर सके।

राष्ट्र–निर्माता के रूप में शिक्षक

महिला शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वे केवल पढ़ाने का काम नहीं करतीं, बल्कि लाखों बालिकाओं के लिए प्रेरणा और आदर्श भी बनती हैं। इसी तरह वे सावित्रीबाई फुले की मशाल को आगे बढ़ा रही हैं। अध्ययन बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिला शिक्षकों की उपस्थिति से लड़कियों का स्कूल में नामांकन और पढ़ाई जारी रखने की संभावना बढ़ जाती है। गरीबी के चक्र को तोड़ने और परिवारों को बेहतर भविष्य का सपना दिखाने में उनका योगदान बेहद अहम है।

विकसित भारत की ओर

जैसे–जैसे भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, शिक्षा विकास का प्रमुख वाहक बनी हुई है। विशेषकर महिलाओं की शिक्षा, इसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है- शिक्षित महिलाएँ बेहतर स्वास्थ्य सेवा, कम शिशु मृत्युदर, उच्च पारिवारिक आय और मज़बूत समुदाय सुनिश्चित करती हैं। यूनेस्को के अनुसार, एक लड़की की स्कूली शिक्षा का प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष उसकी भविष्य की आय में 10–20 प्रतिशत की वृद्धि करता है। इसलिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अपनी योजनाओं को सतत विकास लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्णशिक्षा) और सतत विकास लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता) के अनुरूप बनाना जारी रखे हुए है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी लड़की पीछे न छूटे।हम शिक्षा को पोषण, सुरक्षा और कौशल विकास के साथ जोड़कर ऐसा माहौल तैयार कर रहे हैं जहाँ महिलाएँ विद्यार्थी, शिक्षक, उद्यमी और नेता बनकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें।

सामूहिक संकल्प

सावित्रीबाई फुले की कहानी हमें इस बात की याद दिलाती है कि सच्ची प्रगति साहस से ही जन्म लेती है। पुणे की उनकी साधारण कक्षा से लेकर आधुनिक भारत की उन कक्षाओं तक, जहाँ करोड़ों लड़कियाँ प्रतिदिन शिक्षाग्रहण करती हैं, यह यात्रा महिलाओं और शिक्षा के प्रति समाज के दृष्टिकोण में आए व्?यापक बदलाव को दर्शाती है।लेकिन यह मिशन अभी अधूरा है।

शिक्षक दिवस को मनाते हुए, आइए हम उनके विजन और हमारे प्रधानमंत्री के इस आह्वान के प्रति स्वयं को पुन:समर्पित करें कि महिला सशक्तिकरण कल्याण नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति का विषय है।यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक लड़की शिक्षित हो, प्रत्येक महिला सशक्त हो और प्रत्येक शिक्षक का सम्मान हो, हम अपने सपनों का भारत बना सकते हैं।

सावित्रीबाई फुले की विरासत केवल इतिहास नहीं है – यह हमारे वर्तमान के लिए जीवंत मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रकाशस्तंभ है। उनके साहस के प्रकाश में हम यह देख सकते हैं कि विकसित भारत का मार्ग उसके बेटियों और बेटों द्वारा समान रूप से नेतृत्व किया जाएगा।